अध्याय II

भवन निर्माण विभाग

2 झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (झा.रा.भ.नि.नि.लि.) नवंबर 2015 में स्थापित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी प्राथमिक भूमिका झारखंड में सार्वजनिक अवसंरचना और सरकारी परियोजनाओं के निर्माण, विकास और रख-रखाव का प्रबंधन करना है। कंपनी का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों को कुशल परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते हुये राज्य के अवसंरचना के विकास में सहयोग करना है।

कंपनी का प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके पदेन अध्यक्ष, प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखंड सरकार (झा.स.) होते हैं। बोर्ड में एक प्रबंध निदेशक सहित नौ पदेन निदेशक हैं। राँची स्थित मुख्यालय वाली इस कम्पनी की 24 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ (प.का.इ) हैं, जिनका नेतृत्व जिला स्तर पर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जो क्षेत्रिय स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अनुश्रवण का काम करते हैं।

कंपनी ने ₹14,020.46 करोड़ की कुल लागत के साथ 1,328 कार्य (स्थापना से मार्च 2023 तक) आरंभ किये थे। इसमें से, ₹4,291.07 करोड़ मूल्य के 726 कार्य पूरे किए गए; 218 कार्य प्रगति पर थे (₹1,630.80 करोड़); 272 कार्य प्रारंभिक चरणों में थे; और 112 कार्यों (₹ 194.92 करोड़) को भूमि की अनुपलब्धता, जन विरोध, संवेदकों द्वारा विलम्ब आदि के कारण या तो रोक दिया गया या छोड़ दिया गया।

कंपनी के बजट, योजना, परियोजना कार्यान्वयन और अनुश्रवण की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए 'झा.रा.भ.नि.नि.लि. की कार्यप्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन, योजना, मानव संसाधन प्रबंधन,

परियोजना कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण में कमियों को पाया, जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ/अत्यधिक/निष्फल व्यय, अनुबंध प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी और कार्यों के निष्पादन में लागत/ समय में वृद्धि हुई।

कंपनी ने 24 कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त ₹60.95 करोड़ वापस नहीं किए थे और ये कार्य बाद में छोड़ दिये गये थे, और ये राशि चार से सात साल तक की अवधि के लिए इसके पर्सनल लेजर खाता (पी.एल. खाता) में रखी गयी थी। कंपनी ने तकनीकी समिति का भी गठन नहीं किया था, जैसा कि परिकल्पित है, और परामर्शी द्वारा तैयार किए गए मानक प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वास्तविक स्थल स्थिति के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन के बिना परियोजनाओं का निष्पादन शुरू किया था। इसके अलावा, विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक भूमि या तो उपयोगकर्ता विभागों द्वारा विलम्ब के साथ सौंपी गई थी या नहीं सौंपी गई थी। इसके परिणामस्वरूप कार्यों को रोक दिया गया या छोड़ दिया गया और साथ ही साथ समय और लागत में वृद्धि भी हुई।

प.का.इ. में कर्मचारियों की, विशेष रूप से सहायक अभियंताओं (88 प्रतिशत) और कनीय अभियंताओं (75 प्रतिशत) के पदों पर मानव बल की भारी कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुई।

कंपनी के द्वारा कार्यों के आवंटन में एक समान प्रणाली का पालन नहीं किया गया और संवेदकों को अनियमित रूप से कार्य आवंटित किए गए। बोली लगाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए, कंपनी ने निष्पादित सिविल आभियंत्रिकी कार्यों के अधिकतम मूल्य पर विचार करने के स्थान पर संवेदकों के वार्षिक खातों मे दर्शायी गयी कुल अनुबंध कार्यों के संचालन से कुल प्राप्ति के आधार पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य बोलीदाताओं का चयन हुआ।

कार्यों के निष्पादन में खामियो के कारण संवेदकों को अतिरिक्त भुगतान के कई उदाहरण देखे गए। सात परियोजनाओं में, मूल्य समायोजन के गलत

निर्धारण के कारण ₹1.76 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। डिग्री कॉलेजों के भवनों के निर्माण के लिए, आवश्यक तीन-स्टॉप लिफ्टों के बजाय दो , छह -स्टॉप यात्री लिफ्टों के लिए प्रावधान किए गए थे, जिससे ₹2.60 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था, तथा 11 नमूना जांचित कार्यों में ₹2.15 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान में किया गया।

झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य जून 2018 में शुरु किया गया था,जिसे मई 2020 तक पुरा किया जाना था, लेकिन दिसंबर 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। तदंतर, ₹12.10 करोड़ व्यय करने के बाद जुलाई 2021 में कार्य बंद कर दिया गया था। अर्ध-निर्मित संरचना तब से निष्क्रिय पड़ी थी। इसी तरह, छह परियोजनाओं (चार उपयोगकर्ता विभागों के लिए) से संबंधित कार्यों को आंशिक पूरा होने के बाद और ₹13.32 करोड़ का व्यय करने के बाद बीच में ही रोक/छोड़ दिया गया।

कार्य निष्पादन के दौरान उचित अनुश्रवण के अभाव में, नौ उपयोगकर्ता विभागों से संबंधित 33 कार्य ₹1,698.87 करोड़ के भुगतान के बाद 96 और 1,379 दिनों के बीच के विलम्ब के साथ पूर्ण किए गए और चार उपयोगकर्ता विभागों से संबंधित 14 कार्य, ₹669.98 करोड़ के व्यय और 681 और 2,678 दिनों के विलम्ब के बावजूद अपूर्ण रहे।

पांच कार्यों में, संवेदकों को समय-विस्तार की अनुमति दी गई थी क्योंकि कार्य स्थलों को सौंपने में विलम्ब, कार्य के नक्शा और रूपांकण आदि की उपलब्धता में विलम्ब आदि के कारण कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हुई थी और इस विस्तारित अवधि के दौरान मूल्य समायोजन के रुप में ₹38.98 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप इन पांच कार्यों की लागत पर ₹38.98 करोड़ की वृद्धि हुई।

छियालिस पूर्ण किए गए नमूना-जांचित कार्यों में से 37 कार्य, 837 दिनों तक के विलम्ब के साथ उपयोगकर्ता विभागों को सौंपे गए थे और शेष नौ कार्य उनके पूरा होने के बाद 1,414 दिनों तक के विलम्ब के बाद भी नहीं सौंपे गए थे। परिणामस्वरूप, एक कार्य (₹31.19 करोड़ के व्यय के बाद

फरवरी 2019 में पूर्ण) की कई वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गईं या चोरी हो गई थीं।

कंपनी ने तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी वि.प.प्र. का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी समिति का गठन नहीं किया था। भवन सामग्री का पूर्व-परीक्षण करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया था और न ही कार्यों के नक्शा और रूपांकन बदलाव को मंजूरी देने के लिए कम्पनी के अंदर रूपांकन शाखा स्थापित किया गया था। पाकुड़ में 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया (सितंबर 2022) और संवेदक को ₹10.44 करोड़ का भुगतान किया गया। हालांकि, कोल्ड स्टोरेज का पूर्ण भवन जुलाई 2024 तक उपयोगकर्ता विभाग को नहीं सौंपा जा सका क्योंकि कार्य की जांच के दौरान कंपनी द्वारा गठित समिति द्वारा बताये गये त्रुटियो को संवेदक द्वारा ठीक नहीं किया गया था।

कंपनी ने 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम के उल्लंघन करते हुए आवश्यक आठ वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के विरूध सिर्फ चार वार्षिक आम बैठकें आयोजित कीं। कंपनी ने अपने संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दिसंबर 2020 के बाद ए.जी.एम. आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की।

2.1 परिचय

झारखंड सरकार (झा.स.) के पूर्ण स्वामित्व वाली और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत (दिसंबर 2015) कंपनी, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (झा.रा.भ.नि.नि.लि.) की स्थापना (नवंबर 2015) सार्वजनिक कार्यों के निर्माण, निष्पादन, सुधार, परिवर्तन, विकास, प्रशासन, प्रबंध या नियंत्रण के लिए, सभी प्रकार[1] की सरकारी परियोजनाओं, कार्यालयों, आवासो और अन्य सभी सुविधाओं से सम्बंधित कार्यों के निर्माण

[1] टाउनशिप, सड़कें, पुल, नहर, जलाशय, तटबंध, उद्धार, सुधार, सीवेज, जल निकासी, सफाई, जल, गैस, बिजली, रोशनी, टेलीफोन और बिजली आपूर्ति कार्य, बाजार, मनोरंजन के स्थान, आनंद के मैदान, पार्क, उद्यान, जल-सीवेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र।

लिए की गई थी। कंपनी का उद्देश्य झा.स. के विभिन्न विभागों को सर्वोत्तम परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करके राज्य में बुनियादी ढांचो के विकास की सुविधा प्रदान करना है।

कंपनी (झा.रा.भ.नि.नि.लि.) का प्रबंधन, निदेशक मंडल (नि.मं.) द्वारा किया जाता है, जिसके पदेन अध्यक्ष, भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.), झा.स. के प्रधान सचिव/सचिव होते हैं, और इसमें एक प्रबंध निदेशक (प्र.नि.) को सम्मिलित करते हुये नौ पदेन निदेशक[2] होते हैं। प्र.नि. कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मु.क.अ.) होते है जिसकी सहायता एक कार्यकारी निदेशक (का.नि.) और पांच महाप्रबंधक (म.प्र.) करते हैं। रांची स्थित मुख्यालय वाली इस कम्पनी की 24 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां (प.का.इ.) हैं जिनका नेतृत्व जिला स्तर पर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है,जो क्षेत्रीय स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अनुश्रवण का काम करते हैं।

कंपनी के पास म.प्र. (वित्त और लेखा) के अधीन एक अलग वित्त और लेखा शाखा है, जिसमें एक उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), एक मुख्य लेखा अधिकारी, तीन लेखा अधिकारियों और तीन लेखाकारों द्वारा सभी विपत्रो की जांच करने एवम खातों को तैयार और संधारित करने का काम किया जाता है।कंपनी के सभी कार्यालयों (मुख्यालय/ क्षेत्रीय /प्रमंडल/अनुमंडल कार्यालय) को समय-समय पर निर्धारित सभी बही-खातों को संधारित रखना है, और कंपनी के कार्यों के निष्पादन के लिये लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) संहिता और झारखंड वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन करना है।

कंपनी ने झा.स. के विभागों/एजेंसियों[3] से संबंधित 1,328 परियोजनाएं आरम्भ किया (स्थापना से मार्च 2023 तक) जिनकी कुल परियोजना लागत

---

[2] (1) अध्यक्ष (2) सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (3) सचिव, गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (4) सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग (5) सचिव, ऊर्जा विभाग (6) सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (7) सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग (8) सचिव, राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग और (9) प्र. नि., झा.रा.भ.नि.नि.लि.

[3] राज्य भूगर्भीय संग्रहालय, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग आदि

₹14,020.46 करोड़ थी। मार्च 2023 तक, 726 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं (अनुमानित मूल्य: ₹4,291.07 करोड़); 218 प्रगति पर थे (अनुमानित मूल्य: ₹1,630.80 करोड़); 272 प्रारंभिक चरणों[4] में थे और 112 को (अनुमानित मूल्य: ₹194.92 करोड़) भूमि की अनुपलब्धता, सार्वजनिक बाधाओं, संवेदकों द्वारा विलम्ब आदि के कारण या तो रोक दिया गया था या छोड़ दिया गया था।

कंपनी द्वारा किए गए ये सभी कार्य, जमा कार्य थे, जिसके लिए उपयोगकर्ता विभागों द्वारा अग्रिम धनराशि जमा किया गया था। कंपनी ने खुली बोली के माध्यम से चयनित संवेदकों द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य विभागों/एजेंसियों से परामर्श शुल्क[5] भी लिया। 2018-19 से 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त और उपयोग की गई निधियों का विवरण **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त और कार्यों के लिए उपयोग की गई धनराशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	उपयोग की गई राशि	उपयोग की गई राशि का प्रतिशत	अंतशेष
2018-19	1,268.97	1,354.56	2,623.53	897.69	34.22	1,725.84
2019-20	1,725.84	1,122.52	2,848.36	1,036.02	36.37	1,812.34
2020-21	1,812.34	1,055.52	2,867.86	1,132.85	39.50	1,735.01
2021-22	1,735.01	923.92	2,658.93	1,163.14	43.74	1,495.79
2022-23	1,495.79	1,486.83	2,982.62	1,024.79	34.36	1,957.83
कुल		**5,943.35**		**5,254.49**		

(स्रोत: झा.रा.भ.नि.नि.लि.)

[4] वि.प.प्र. चरण, प्रशासनिक अनुमोदन के लिए भेजा गया, निविदा प्रक्रिया में या कार्य शुरू होनेवाला था।

[5] (ए) ₹10 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए = सात *प्रतिशत*; (बी) ₹10 करोड़ से अधिक और ₹100 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए = (ए) + ₹10 करोड़ से अधिक की राशि पर पांच *प्रतिशत*; (सी) ₹100 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए = (बी) + ₹100 करोड़ से अधिक की राशि पर एक *प्रतिशत*।

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि उपलब्ध निधियों में से, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान केवल 34.22 और 43.74 *प्रतिशत* के बीच की राशि का उपयोग किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यों को प्रारंभ करने में विलम्ब, कार्यों की धीमी प्रगति और कार्यों को बीच में रोकने/छोड़ने के कारण राशि का कम उपयोग हुआ था, जैसा कि ***कंडिकाएँ 2.5.2.1*** *और* ***2.5.5.2*** में चर्चा की गयी है।

पिछले लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अकुशल प्रबंधन और परियोजनाओं के निष्पादन में अनियमितताओं को देखते हुए कंपनी की कार्यप्रणाली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया।

2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

- कॉर्पोरेट बजट तैयार किया गया था, और राशि आवंटन और वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था;
- परियोजनाओं के लिए योजना प्रक्रिया प्रभावी थी;
- परियोजनाओं का निष्पादन मितव्ययी, कुशल और प्रभावी था;
- एक प्रभावी अनुश्रवन और मूल्यंकन तंत्र स्थापित किया गया था; और
- एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और शिकायत निवारण प्रणाली लागू थी।

2.3 लेखापरीक्षा के मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से अपनाए गए थे:

- एसोसिएशन के ज्ञापन, एसोसिएशन के लेख, व्यय विनियमन, शक्तियों का प्रत्यायोजन, व्यवसाय के नियम और नि.मं. की बैठकों में पारित संकल्प
- झारखंड लोक निर्माण विभाग (झ.लो.नि.वि.) सन्हिता, झारखंड लोक निर्माण लेखा (झ.लो.नि.ले.) संहिता, झारखंड वित्तीय नियमों और प्रासंगिक परिपत्रों और निर्देशों के प्रावधान; और

- ❖ भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा जारी परिपत्र, अधिसूचनाएं, संकल्प और अन्य निर्देश।

2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि को आच्छादित करते हुये यह निष्पादन लेखापरीक्षा, कंपनी-मुख्यालय और जिला स्तर पर 24 में से 12[6] प.का.इ. के अभिलेखो की नमूना-जांच के माध्यम से मई 2023 और अक्टूबर 2023 के बीच किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा किए गए व्यय की मात्रा के आधार पर 206 परियोजनाओं (94 परियोजनाएं[7] और सभी 112 रोके/ छोड़े गये परियोजनाएं) का चयन विस्तृत जांच के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा पद्धति में कंपनी मुख्यालय और प.का.इ. में अभिलेखों की जांच, कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ परियोजनाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन, और कंपनी को जारी प्रश्नावली की प्रतिक्रियाओं की जांच शामिल थी।

सचिव, भवन निर्माण विभाग-सह-प्रबंध निदेशक, झा.रा.भ.नि.नि.लि. के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (13 जून, 2023) आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, क्षेत्र और मानदंडों पर चर्चा किया गया था। भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.) के सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकनो के उत्तर प्रस्तुत किए (जुलाई 2024) जिन्हें प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। 26 सितंबर 2024 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, झा.स. के साथ एक निकास सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें विभाग ने आश्वासन दिया था कि वह लेखापरीक्षा अनुशंसाओ पर सुधारात्मक उपाय करेगा।

---

6 बोकारो, दुमका, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़ और पलामू।

7 कंपनी द्वारा किए गए व्यय की मात्रा के आधार पर, चार स्तरों में परियोजनाओं को स्तरीकृत करने के बाद कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट तकनीक (सी.ए.ए.टी.) के माध्यम से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण द्वारा प्रगतिरत 936 परियोजनाओं में से 10 प्रतिशत का चयन किया गया। इन 94 परियोजनाओं में 68 पूर्ण और 26 प्रगति परियोजनाएं शामिल हैं।

2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए कंपनी झारखंड वित्तीय नियमों और झारखंड लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अलावा, कंपनी के एसोसिएशन लेख, एसोसिएशन ज्ञापन और व्यवसाय के नियमों द्वारा शासित होती है। लेखापरीक्षा में अपर्याप्त योजना, उचित वित्तीय प्रबंधन की कमी, परियोजना प्रबंधन में अनियमितताओं और अनुश्रवण की कमी के मामले पाये गये, जिसके परिणामस्वरूप अपव्यय, निष्फल, अनियमित और परिहार्य व्यय के साथ-साथ उपयोगकर्ता विभागों को विभिन्न परियोजनाओं को सौपने में लागत और समय में वृद्धि हुई, जैसा कि बाद के कंडिकाओ में चर्चा की गई है।

2.5.1 वित्तीय प्रबंध

2.5.1.1 वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम **तालिका 2.2** में दिए गए हैं।

तालिका 2.2: कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम

(₹ करोड़ में)

वित्तीय स्थिति					
निधियों का स्रोत					
मद	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**
शेयर पूंजी	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
भंडार और अधिशेष	36.33	55.28	68.07	97.56	117.02
झा.स. और अन्य संस्थानों से प्राप्त अग्रिम	1,729.95	1,783.75	1,706.42	1,467.19	1,929.24
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	124.75	190.21	280.35	324.42	307.75
कुल	**1,893.03**	**2,031.24**	**2,056.84**	**1,891.17**	**2,356.01**
मद	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**
निधियों का अनुप्रयोग:					
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	0	0	0	0	0
नकद और नकद समतुल्य	1,883.99	2,023.25	2,055.70	1,883.48	2345.02
अन्य चालू परिसंपत्तियां	8.56	7.53	0.84	6.90	7.70
कुल	**1,892.55**	**2,030.78**	**2,056.54**	**1,890.38**	**2,352.72**
कार्य परिणाम					

संचालन से राजस्व	40.72	40.27	28.71	49.25	36.33
बैंक से ब्याज	0.41	0.41	0.08	0.25	1.28
कुल	**41.13**	**40.68**	**28.79**	**49.50**	**37.61**
व्यय					
वित्त लागत	0	0	0	0	0
प्रशासन और अन्य व्यय	11.24	13.81	10.40	9.80	11.22
कुल	**11.24**	**13.81**	**10.40**	**9.80**	**11.22**
कर पूर्व लाभ (हानि)	29.88	26.87	18.39	39.70	26.39
कर	8.85	7.93	5.60	10.21	6.92
कर के बाद शुद्ध लाभ (हानि)	**21.03**	**18.94**	**12.79**	**29.49**	**19.47**

स्रोत: झा.रा.भ.नि.नि.लि.के लेखा (2022-23 के लेखा अंतरिम हैं)

कंपनी के वित्तीय प्रबंध की समीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- झारखंड कोषागार सन्हिता के नियम 334 के अनुसार, प्रशासक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पर्सनल लेजर खातों (पी.एल.खाता) में जमा राशि की समीक्षा करनी होगी। लगातार दो वित्तीय वर्षों के बाद खर्च न किए गए राशि को आगे खर्च नहीं किया जाना चाहिए, और शेष राशि को व्यय में कमी के रूप में, संबंधित सेवा शीर्ष जिससे राशि की निकासी की गयी थी, मे स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान पांच[8] उपयोगकर्ता विभागों से 24 कार्यों[9] के निष्पादन के लिए ₹

[8] कृषि, पशुपालन और सहकारिता; स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण; स्कूली शिक्षा और साक्षरता; पर्यटन, कला संस्कृति, खेल और युवा मामले और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण

[9] कृषि, पशुपालन और सहकारी विभाग के जिला गव्य विकास कार्यालय, जमशेदपुर (₹ 0.63 करोड़) का निर्माण; स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 12 प्रा.स्वा.के.(₹ 21.13 करोड़), एक सा.स्व.के. (₹ 10.58 करोड़), राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय चाईबासा के लिये 50 बिस्तरों वाली महिला छात्रावास (₹ 1.00 करोड़), डॉक्टर का आवास (₹ 1.25 करोड़) और चिकित्सा सहायक/नर्सों के लिए (₹ 1.00 करोड़) आवास; स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत दो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण (₹ 6.99 करोड़), पर्यटन, कला संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग के अंतर्गत उर्वा मे कौटेज और दशम झरना के पास पर्यटन विकास (₹ 3.37 करोड़) का निर्माण और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत तीन आश्रम विद्यालयो का निर्माण (₹ 15 करोड़)

60.95 करोड़[10] प्राप्त हुए थे जिसे उसने अपने पी.एल. खाते में जमा की थी। इन सभी कार्यों को (सितंबर 2017 और दिसंबर 2022 के बीच) भूमि की अनुपलब्धता (19 कार्य), भूमि की उपलब्धता में विलम्ब (दो कार्य) और राशि प्रदान करने के बाद उपयोगकर्ता विभागों द्वारा संबंधित दस्तावेजों के अहस्तांतरण के कारण छोड़ दिया गया था (दो कार्य)। इसके अलावा, उपयोगकर्ता विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताए एक कार्य छोड़ दिया गया था। चूंकि कार्यों के निष्पादन के लिए कंपनी द्वारा ₹60.95 करोड़ की जमा राशि का उपयोग (मार्च 2023 तक) नहीं किया जा सका था, इसलिए इसे उपयोगकर्ता विभागों को वापस करना आवश्यक था। हालांकि, यह राशि चार से सात वर्ष के बीच की अवधि के लिए कंपनी के पी.एल. खाते में पड़ी थी (जुलाई 2024 तक)।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि कोषागार पी.एल. खाते की जांच की जाएगी और लगातार दो वर्षों से अधिक समय तक रखे गए शेष को प्रशासनिक विभागों को वापस कर दिया जाएगा।

अनुशंसा 1: कंपनी उपयोगकर्ता विभागों को अपने पी.एल. खाते में पड़ी अप्रयुक्त निधियों की समय पर वापसी सुनिश्चित कर सकती है।

2.5.2 योजना

कंपनी के व्यवसाय के नियमों में कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति के गठन का प्रावधान है जो सभी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) और परियोजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं; यदि आवश्यक हो तो संशोधनों का सुझाव देना, और कार्यों के आवंटन, प्रगति और निष्पादित कार्य की गुणवत्ता आदि सहित सभी स्वीकृत परियोजनाओं/योजनाओं का अनुश्रवण करेगी।

कंपनी के व्यवसाय के नियम कॉर्पोरेट बजट तैयार करने की एक उचित प्रणाली भी प्रदान करते हैं जिसमें चल रही परियोजनाओं की स्थिति, शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं, वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले

[10] 2016-17: ₹ 30.85 करोड़, 2017-18: ₹ 19.53 करोड़, 2018-19: ₹ 2.76 करोड़ और 2019-20: ₹ 7.81 करोड़

कार्यों के मूल्य, आवश्यक योजनाओं की संख्या, स्वीकृत योजनाओं और शेष योजनाओं को तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन आदि शामिल है।

कंपनी के अभिलेखो की जांच से उद्घटित हुआ कि उसने वि.प.प्र. की समीक्षा करने और कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान न तो कॉर्पोरेट बजट तैयार किया था और न ही तकनीकी समिति का गठन किया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपयोगकर्ता विभागों से प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) प्राप्त करने के लिए मॉडल प्राक्कलनो[11] के आधार पर परामर्शी द्वारा वि.प.प्र. तैयार किए गए थे। कार्यों का निष्पादन तकनीकी समिति द्वारा बिना मूल्यांकन किये गये मॉडल प्राक्कलनो के आधार पर प्राप्त प्र.अ. के बाद शुरू किए गए।

झारखंड लोक निर्माण विभाग (झा.लो.नि.वि.) संहिता (नियम 126 और 130), सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक कार्य के लिए एक उचित विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना निर्धारित करता है। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि परियोजनाओं को स्थल विशिष्ट नक्शों और रूपांकणो के बिना तथा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना शुरू किया गया था। इसके कारण कार्यों को छोड़ दिया गया/रोक दिया गया साथ ही साथ लागत और समय में वृद्धि हुई, जैसा कि निम्नलिखित कंडिका में चर्चा की गई है।

2.5.2.1 कार्य रूक गया

झा.लो.नि.वि. संहिता (नियम 132) निर्धारित करता है कि, दरारों की मरम्मत आदि जैसे तत्काल कार्यों को छोड़कर, ऐसी भूमि पर कोई कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए जिसे एक जिम्मेदार सिविल अधिकारी द्वारा विधिवत रुप से अधिगृहित नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि

[11] प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परियोजना की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जरूरी नही कि वास्तविक स्थल स्थिति के आधार पर नहीं। कार्य का निष्पादन शुरू करने के लिए, वास्तविक स्थल स्थिति के आधार पर एक विस्तृत प्राक्कलन आवश्यक है।

तीन[12] उपयोगकर्ता विभागों द्वारा (अक्टूबर 2010 और मार्च 2017 के बीच) ₹102.87 करोड़ मूल्य के 35 कार्यों[13] का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था। इन कार्यों का निष्पादन कंपनी को सौंपा गया था, और कंपनी को 14 कार्यों के लिये ₹ 42.45 करोड़ रुपये (2016-17 और 2019-20 के बीच) निर्गत किए गए थे। शेष 21 कार्यों के लिए, संबंधित विभागों द्वारा कंपनी को कोई राशि निर्गत नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने फरवरी 2018 और जुलाई 2019 के बीच पूर्ण होने की निर्धारित तिथियो के साथ सभी 35 कार्यों के निष्पादन के लिए संवेदकों के साथ कुल ₹102.54 करोड़ मूल्य का अनुबंध किया (नवंबर 2016 और अप्रैल 2018 के बीच)। हालांकि, कंपनी द्वारा सभी 35 कार्यों को (अक्टूबर 2019 और दिसंबर 2022 के बीच) छोड़ दिया गया था, क्योंकि 33 कार्यों के मामले में उपयोगकर्ता विभागों द्वारा निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जबकि दो कार्यों के मामले में देरी हुई थी। इस प्रकार, कंपनी संहिता प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य शुरू करने से पहले उपयोगकर्ता विभागों के साथ समन्वय करके भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसके कारण इन कार्यों को आरंभ नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि सभी 35 योजनाओं को छोड़ दिया गया था क्योंकि उपयोगकर्ता विभागों द्वारा भूमि प्रदान नहीं की गई थी। भूमि प्राप्त होने की प्रत्याशा में, कंपनी ने निविदाएं आमंत्रित की थीं और संवेदकों को कार्य आवंटित किया गया था। कंपनी ने आगे कहा कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।

2.5.2.2 लागत और समय में वृद्धि

---

[12] अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण; स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग।

[13] आश्रम स्कूलों (02), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (07), एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज, चाईबासा में एक 50 बिस्तरों वाली लड़कियों के छात्रावास, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चाईबासा मे एक चिकित्सा सहायक/नर्स आवास, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय (08), लड़कियों के छात्रावास (09) और मॉडल स्कूल (06) का निर्माण ।

झा.लो.नि.वि. संहिता (नियम 126 और 130) में प्रावधान है कि एक समुचित विस्तृत प्राक्कलन, जिसे 'तकनीकी स्वीकृति' (त.स्वी.) के रूप में जाना जाता है, को प्रस्तावित प्रत्येक कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए तैयार किया जाना चाहिए। विस्तृत प्राक्कलन, दरों की प्रचलित अनुसूची (एस.ओ.आर.) में दी गई मात्रा और दरों पर आधारित होना चाहिए और उपयोगकर्ता विभागों के गैर-तकनीकी अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए।

सात विभागों[14] ने डिग्री कॉलेजों, बहुउद्देशीय परीक्षा भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सा.स्वा.के.), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के.), महिला छात्रावास, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण से संबंधित 31 कार्यों जिनका मूल्य मॉडल प्राक्कलन के आधार पर ₹335 करोड़ था, का प्रशासनिक अनुमोदन किया था (अक्टूबर 2013 और अक्टूबर 2020 के बीच) ***(परिशिष्ट 2.1)***, और जिसके निष्पादन का कार्य कंपनी को सौंपा गया था। कंपनी ने तकनीकी समिति की अनुपस्थिति में परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित किए बिना, और वास्तविक स्थल स्थिति के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए बिना मई 2018 और फरवरी 2023 के बीच इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न संवेदकों के साथ ₹293.85 करोड़ मूल्य का अनुबंध किया किया था (दिसंबर 2016 और अगस्त 2021 के बीच)। लेखापरीक्षा ने पाया कि झ.लो.नि.स. के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विस्तृत नक्शा और रूपांकण की उपलब्धता के अभाव में मॉडल प्राक्कलनो के आधार पर संवेदकों द्वारा कार्यों को निष्पादित किया गया था।

परिणामस्वरुप, ₹258.61 करोड़ की लागत से 25 कार्य, चार से 54 महीने तक के विलम्ब से पूर्ण किये गये थे। आगे, यह भी देखा गया कि जुलाई 2024 तक तीन कार्य, अपने पूर्ण होने की निर्धारित तिथियो से 18 से 65

[14] उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास: 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण: 05, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण: 02, कृषि, पशुपालन और सहकारिता: 02, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले: 02, स्कूली शिक्षा और साक्षरता: 02 और श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास: 01 ।

महीने के विलम्ब के बाद और ₹21.32 करोड़ का व्यय करने के पश्चात प्रगति पर थे। ये कार्य संबंधित अनुबंधो को अंतिम रूप देने के बाद संवेदकों को विलम्ब से स्थलों और नक्शा/रूपांकण उपलब्ध कराने के कारण अपूर्ण थे। जुलाई 2024 तक, 23 कार्यों में ₹31.06 करोड़ की लागत में वृद्धि भी देखी गई थी क्योंकि कार्यों की मदों की अनुबंधित मात्रा के विरुद्ध मूल्य भिन्नता का भुगतान किया गया था। यह वास्तविक स्थल स्थिति के अनुसार विस्तृत प्रक्कलनो के अभाव के कारण हुआ था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि कंपनी ने उपयोगकर्ता विभागों की मांग पर मॉडल प्राक्कलन प्रदान किए थे। उपयोगकर्ता विभागों ने कार्य को निष्पादित करने के लिए भूमि प्रदान किए बिना इन मॉडल प्राक्कलनो के आधार पर प्र.अ. निर्गत किया था। इसके अलावा कंपनी वास्तविक स्थल की स्थिति के अनुसार नक्शा भी तैयार नहीं कर सकी, जिसके कारण परियोजना लागत में वृद्धि हुई।

इस प्रकार, उपयोगकर्ता विभागों ने परियोजनाओं के तकनीकी रूप से अनुमोदित मॉडल प्राक्कलनो के आधार पर प्र.अ. को मंजूरी दी थी, हालांकि, झा.लो.नि.संहिता अनुसार, वास्तविक स्थल की स्थिति के अनुसार विस्तृत नक्शा/रूपांकण के आधार पर कार्यों के प्राक्कलनो के लिए तकनीकी स्वीकृति, कार्य के निष्पादन के लिए एक शर्त थी। इसके अलावा, प्राक्कलनो की जांच करने के लिए एक तकनीकी समिति की अनुपस्थिति में, कंपनी ने विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए बिना, केवल माल और सेवा कर (जीएसटी), श्रम शुल्क और सेंटेज शुल्क जोड़कर उसी मॉडल प्राक्कलनो पर तकनीकी स्वीकृति दी, और कार्यों का निष्पादन शुरू किया। वास्तविक स्थल स्थिति के आधार पर विस्तृत नक्शा और रूपांकण, अनुबंध निष्पादित करने के बाद ही तैयार किए गए थे, जिसके कारण परियोजना लागत में वृद्धि हुई, जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

- ***डिग्री कॉलेजों का निर्माण***

कंपनी ने प्रत्येक पर ₹15.77 करोड़ की लागत से 27 डिग्री कॉलेजों[15] के निर्माण के लिए एक मॉडल प्राक्कलन तैयार किया था (नवंबर 2016)। मॉडल प्राक्कलन के आधार पर, उपयोगकर्ता विभाग (उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास) ने ₹425.79 करोड़ (प्रत्येक डिग्री कॉलेज के लिए ₹15.77 करोड़) के लिए प्र.अ. प्रदान (फरवरी 2017 और अगस्त 2018 के बीच) किया था। निविदा के बाद, 27 डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए अनुबंध की तारीख से 24 महीने के भीतर पूर्ण करने हेतु विभिन्न संवेदकों के साथ ₹382.14 करोड़ मूल्य के अनुबंध निष्पादित किया गया था (सितंबर 2017 और जनवरी 2020 के बीच)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संवेदकों द्वारा 20 डिग्री कॉलेजों का निर्माण कार्य (₹ 292.74 करोड़ की लागत से) समय पर पूरा कर लिया गया था। हालांकि, 22 से 34 महीने के विलम्ब के साथ, ₹62.11 करोड़ का व्यय करने के बाद भी, अक्टूबर 2023 तक छह डिग्री कॉलेजों का कार्य प्रगति पर था। एक डिग्री कॉलेज[16] का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका क्योंकि सीमांकित भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत थी और कंपनी वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए वन विभाग के पोर्टल पर आवश्यक विवरण अपलोड करने में असमर्थ थी।

27 डिग्री कॉलेजों में से 13[17] जिसके लिए कंपनी को भूमि उपलब्ध कराई गई थी (अक्टूबर 2016 और जनवरी 2019 के बीच), के निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच में उद्घटित हआ कि सितंबर 2019 और अगस्त 2021 के बीच कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदकों के साथ ₹179.45

---

15 बानो (सिमडेगा), बरही (हजारीबाग), बिशुनपुर (गुमला), भावनाथपुर (गढ़वा), बरकट्टा (हजारीबाग), बोरियो, बरहेट (साहिबगंज), छतरपुर (पलामू), डुमरी, पीरटांड (गिरिडीह), गोमिया (बोकारो), हुसैनाबाद (पलामू), जगन्नाथपुर (पश्चिम सिंहभूम), झरिया, (धनबाद), खरसावां (सरायकेला-खरसावां), कोलेबिरा (सिमडेगा), खिजरी (रांची), महेशपुर (पाकुड़), महगामा (गोड्डा), मझगांव (पश्चिम सिंहभूम), मनोहरपुर (चाईबासा), मनिका (लातेहर), नाला (जामतारा), सिकारीपारा, जरमुंडी (दुमका), सतगामा (कोडरमा) और टुंडी (धनबाद)।

16 डिग्री कॉलेज, बोरियो, साहिबगंज।

17 बरही, छतरपुर, गोमिया, जरमुंडी, खरसावां, खिजरी, मणिका, महगामा, महेशपुर, मनोहरपुर, नाला, शिकारीपारा और टुंडी।

करोड़ मूल्य का अनुबंध निष्पादित किया गया था (सितंबर 2017 और अगस्त 2019 के बीच)।13 में से 12 कार्य ₹177.98 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किए गए थे और शेष कार्य (डिग्री कॉलेज, गोमिया, बोकारो) पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 31 महीने के बीत जाने (अक्टूबर 2023 तक) और ₹11.97 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्रगति पर थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इन 13 डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए सामान्य व्यवस्था नक्शा[18] (जी.ए.डी.) मॉडल प्राक्कलनो के अनुसार थे और परामर्शी द्वारा परियोजना की लागत को वास्तविक स्थल की स्थिति के अनुसार नहीं निकाला गया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि इन कॉलेजों के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई थी (अक्टूबर 2016 और जनवरी 2019 के बीच) और परामर्शी ने कंपनी को डिग्री कॉलेज के प्राक्कलन प्रस्तुत (नवंबर 2017 और अक्टूबर 2020 के बीच) किए थे।

इसके अलावा, एक तकनीकी समिति की अनुपस्थिति में, कंपनी ने वास्तविक स्थल या विस्तृत नक्शा/रूपांकण के अनुसार कार्य की लागत का पता नहीं लगाया, लेकिन मॉडल प्राक्कलनो में केवल जी.एस.टी., श्रम शुल्क और सेंटेज शुल्क को जोड़कर तैयार किए गए प्राक्कलनो पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी (जुलाई 2017 और जनवरी 2019 के बीच)। हालांकि, वास्तविक स्थल की स्थिति के आधार पर नक्शा के अनुसार, दो कार्यों की विस्तृत परियोजना लागत निकालने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक परियोजना (डिग्री कॉलेज, महेशपुर, पाकुड़) की लागत ₹15.77 करोड़ से बढ़कर ₹18.35 करोड़ हो गई थी, जबकि एक अन्य परियोजना (डिग्री कॉलेज, छतरपुर, पलामू) की लागत ₹15.77 करोड़ से बढ़कर ₹20.39 करोड़ हो गई थी, जैसा कि **तालिका 2.3** में विस्तृत है।

तालिका 2.3: लागत की तुलना

(राशि लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	मॉडल प्राक्कलन के अनुसार लागत	त. स्वी. के अनुसार लागत	वास्तविक नक्शा के अनुसार डिग्री कॉलेज की लागत

[18] जी.ए.डी. का अर्थ एक संरचना का रूपांकण/निर्माण नक्शा है जो विस्तृत लेआउट, आयाम, कनेक्शन और विनिर्देश प्रदान करता है, जो आम तौर पर एक स्थल योजना पर आरोपित होता है।

				महेशपुर, पाकुड़	**छतरपुर, पलामू**
1	निर्माण की लागत	1,381.85	1,433.01	1,521.93	1693.66
2	जी.एस.टी. (12 *प्रतिशत*)	0	171.96	182.63	203.24
3	श्रम शुल्क	13.82	16.05	17.05	18.97
4	झा.रा.भ.नि.नि.लि. शुल्क	89.09	91.65	96.10	104.70
5	समय वृद्धि	78.88	0	0	0
6	सेवा शुल्क	13.36	0	0	0
7	झा.रा.भ.नि.नि.लि. शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी.	0	16.50	17.30	18.85
8	मृदा परीक्षण और स्थल सर्वेक्षण के लिए शुल्क	0	0.69	0	0
कुल		**1,577.00**	**1,729.85**	**1,835.01**	**2,039.42**

(स्रोत: जी.ए.डी. के अनुसार महेशपुर और छतरपुर में डिग्री कॉलेजों का मॉडल प्राक्कलन और लागत प्राक्कलन)

इस प्रकार, इन दो डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए परियोजना लागत में ₹29.19 करोड़ की अनुबंधित लागत से अधिक ₹7.20 करोड़[19] की वृद्धि हुई।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि, परियोजना के लिए भूमि के आवंटन के बाद, परामर्शी द्वारा प्रत्येक परियोजनाओं के लिए स्थल विशिष्ट नक्शा तैयार किया गया था। इससे डिग्री कॉलेजों की मदों की मात्रा और परियोजना लागत में भिन्नता आई।

- उपायुक्त (डी.सी.), रांची ने खिजरी, रांची में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की थी (जून 2018)। परामर्शी ने कंपनी को कॉलेज के कार्य का नक्शा और रूपांकण प्रस्तुत किया था (अगस्त 2018)। एक संवेदक द्वारा ₹12.71 करोड़ के एक संविदा के निष्पादन (नवम्बर 2018) के बाद कार्य शुरू किया गया था (14 फरवरी 2019)। हालांकि, कार्यपालक अभियंता (का.अ.), दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.), रांची ने आपत्ति जताई (21 फरवरी 2019) कि उक्त भूमि पहले ही (2008 में) हाई-टेंशन लाइन के निर्माण के लिए डी.वी.सी. को आवंटित की जा चुकी थी। तदनुसार, कंपनी ने डी.वी.सी. द्वारा हाई-टेंशन लाइन के निर्माण के लिए दोनों भागों के बीच 37.40 मीटर की जगह छोड़ते हुए, दो अलग-अलग हिस्सों में भवन के

[19] डिग्री कॉलेज, महेशपुर: ₹ 2.58 करोड़ और डिग्री कॉलेज, छतरपुर: ₹ 4.62 करोड़।

निर्माण का प्रस्ताव करके कार्य के नक्शा को संशोधित किया (अगस्त 2019)।

तकनीकी समिति की अनुपस्थिति में, रूपांकण की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन नहीं किया गया था, और कंपनी द्वारा निर्माण के लिए उपयोगकर्ता विभाग से कोई वैकल्पिक स्थल नहीं मांगी गई थी। अपने मूल प्रस्ताव से रूपांकण में भौतिक विचलन के बावजूद, कंपनी ने उपयोगकर्ता विभाग से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया जैसा कि झा.लो.नि.सं. के नियम 123 के अंतर्गत आवश्यक है। संवेदक ने संशोधित नक्शा के अनुसार भवन के दो हिस्सों के निर्माण कार्य को निष्पादित किया और डी.वी.सी. ने भवन के दो हिस्सों के बीच हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइन (एच.टी. लाइन) का निर्माण किया। डिग्री कॉलेज का कार्य पूर्ण किया गया (अप्रैल 2022) और कंपनी द्वारा संवेदक को ₹11.39 करोड़ का भुगतान किया गया था (दिसंबर 2022)। हालांकि, हाई-टेंशन लाइन के निर्माण के कारण, प्रबंधक, प.का.इ., रांची और संवेदक की उपस्थिति में कुलपति, रांची विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम निरीक्षण के बावजूद उपयोगकर्ता विभाग (उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास) द्वारा भवन का अधिग्रहण नहीं किया गया था। प्रबंधक प.का.इ., रांची ने कंपनी से डी.वी.सी. के अधिकारियों के परामर्श से विभागीय स्तर पर भवन सौंपने के मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया (जनवरी 2023)। संवेदक ने कंपनी को यह भी याद दिलाया (मार्च 2023) कि फर्नीचर और फिक्सचर के साथ निर्मित भवन की जिम्मेदारी दोष दायित्व अवधि के समाप्ति (अप्रैल 2023) के बाद उसकी नहीं होगी। इस प्रकार, हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के आसपास भवनों के निर्माण के प्रतिकूल प्रभाव का अनुमान लगाने में कंपनी की असमर्थता के कारण निर्मित भवन निष्क्रिय रह गईं, जिससे ₹12 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

विभाग ने कहा **(**जुलाई 2024**)** कि हाई-टेंशन लाईन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। हाई-टेंशन लाईन को स्थानांतरित करने के बाद**,** लेखापरीक्षा को सूचित करते हुये भवन उपयोगकर्ता विभाग को सौंप दिया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि डिग्री कॉलेज के लिए निर्मित भवनों का अप्रैल 2022 में पूरा होने के बाद से उपयोग नहीं किया गया है।

- ***झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण***

झा.लो.नि.वि. सन्हिता के नियम 123 के अनुसार, कार्य के निष्पादन के दौरान दरों में वृद्धि या अन्य कारणों से व्यय में मूल रूप से अनुमोदित राशि के 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के लिए सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रा.अ. प्राप्त किया जाना है।

कंपनी की स्थापना से पहले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झा. स. (उपयोगकर्ता विभाग) द्वारा एक परामर्शी के माध्यम से 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय[20] (झा.बा.आ.वि.) के निर्माण के लिए ₹4.41 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय की लागत से एक मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया था (दिसंबर 2015)। उपयोगकर्ता विभाग ने प्रत्येक झा.बा.आ.वि. के निर्माण के लिए ₹4.48 करोड़ की दर से ₹255.36 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन भी प्रदान (दिसंबर 2015) किया था। कार्य के मॉडल प्राक्कलन के आधार पर, कंपनी ने परामर्शी से जी.ए.डी. प्राप्त किए बिना, प्रत्येक झा.बा.आ.वि. के निर्माण के लिए ₹4.41 करोड़ का प्र. अ. प्रदान किया।

कंपनी ने अनुबंधो की तिथि से 15 महीने के भीतर 57 झा.बा.आ.वि. के कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न संवेदकों के साथ ₹255.53 करोड़ मूल्य के अनुबंधों (नवंबर 2016 और जनवरी 2021 के बीच) को निष्पादित किया। लेखापरीक्षा ने पाया किया कि 57 कार्यों में से, 33 कार्य ₹157.51 करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए थे, 11 कार्य ₹37.53 करोड़ के व्यय के बाद, प्रगति पर थे (अक्टूबर 2023 तक) भूमि की अनुपलब्धता के कारण आठ कार्यों को छोड़ दिया गया (दिसंबर 2021) और पांच कार्यों को रोक

[20] बोकारो: 01, चतरा: 02, देवघर: 02, धनबाद: 03, पूर्वी सिंहभूम: 02, गढ़वा: 05, गिरिडीह: 01, गुमला: 02, गोड्डा: 01, हजारीबाग: 06, लातेहार: 03, लोहरदगा: 02, जामतारा: 02, कोडरमा: 02, खूंटी: 01, पलामू: 08, रामगढ़: 02, रांची: 05, सिमडेगा: 03, सरायकेला-खरसावां: 01 और पश्चिम सिंहभूम: 03

दिया गया (₹12.31 करोड़ के व्यय के बाद) क्योंकि वाणिज्यिक न्यायालय, रांची, झारखंड में संवेदक द्वारा मामले दायर[21] किए गए हैं।

- इसके अलावा, मॉडल प्राक्कलनो के आधार पर 49 झा.बा.आ.वि. (आठ छोड़े गए कार्यों को छोड़कर) का निर्माण शुरू किया गया था और निविदा के माध्यम से संवेदकों के साथ अनुबंधो के निष्पादन के बाद, कंपनी ने उपयोगकर्ता विभाग को सूचित किए बिना नक्शा[22] को बदल दिया। परिणामस्वरुप, विभाग द्वारा कोई संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत नहीं किया गया था। 49 झा.बा.आ.वि. में से चार कार्यों[23] को पुराने रूपांकण के अनुसार पूर्ण किया गया था और 40 कार्यों (पांच रुके हुए कार्यों को छोड़कर) को संशोधित नक्शा के अनुसार निष्पादित किया जाना था। 40 झा.बा.आ.वि. में से, 29 झा.बा.आ.वि ₹141.57 करोड़ की लागत से. पूर्ण किए गए और 11 कार्य ₹37.53 करोड़ व्यय करने के बाद अपूर्ण रहे, जिसमें निर्धारित पूर्णता तिथि (फरवरी 2018 और अप्रैल 2022 के बीच) से 18 से 67 महीने के बीच का विलम्ब था। यह देखा गया कि कंपनी के पास पर्याप्त धन की अनुपलब्धता तथा उपयोगकर्ता विभाग से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव के कारण ये कार्य अपूर्ण रहे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया **(**जुलाई 2024**)** और कहा कि सरकारी दिशानिर्देशों **(**जून 2019**)** के अनुसार**,** बेहतर स्थिरता प्रदान करने के लिए सभी भार वहन संरचनाओं को तैयार संरचनाओं के साथ प्रतिस्थापित किया जाना था। आगे कहा गया कि स्थल विशिष्ट नक्शा के साथ संयुक्त फ्रेमयुक्त संरचना में भार वहन संरचना के रूपांतरण के कारण झा.बा.आ.वि. की परियोजना लागत में वृद्धि हुई थी।

---

21 जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति, प्रतिभूति जमा निर्गत करने आदि के लिए जून 2022 में मध्यस्थता संख्या 10/2022 और 03 जुलाई 2022 में मध्यस्थता संख्या 03/ 2022 दायर की गयी।

22 एक भार वाले संरचना से एक फ्रेम की गई संरचना तक

23 चार झा.बा.आ.वि. (प.का.इ., रांची के अंतर्गत नगरी, रातु, इटकी और राहे प्रखण्ड) को लोड बियरिंग संरचना के नक्शा के अधार पर ₹ 15.94 करोड की लागत पर पूर्ण किया गया और उपयोगकर्ता विभाग को हस्तांतरित किया गया (जुलाई 2019 और अप्रैल 2021 के बीच)

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि नक्शा में परिवर्तन और परियोजना लागत में वृद्धि को आच्छादित करने के लिए संशोधित प्र.अ. प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता विभाग को सूचित करने मे कंपनी की शिथिलता के कारण 11 झा.बा.आ.वि. का निर्माण कार्य लंबी अवधि के बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका।

- मॉडल प्राक्कलन के आधार पर, प.का.इ., गढ़वा द्वारा जुलाई 2018 मे निर्धारित पूर्णता के साथ गढ़वा में तीन झा.बा.आ.वि.[24] के निर्माण के लिए एक संवेदक के साथ ₹12.22 करोड़ मूल्य का एक अनुबंध निष्पादित किया गया था (जनवरी 2017)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो झा.बा.आ.वि. (बिष्णुपुरा और संगमा) के निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुबंध के निष्पादन के बाद आठ से दस महीने के बीच के विलम्ब के साथ भूमि उपलब्ध कराई गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया[25] कि झा.बा.आ.वि., संगमा के लिए निर्धारित स्थल, बल्हा बांध की सिंचाई नहर के पास जल जमाव की संभावना वाले क्षेत्र में स्थित था।

प.का.इ., गढ़वा ने एक संयुक्त निरीक्षण टीम[26] द्वारा सत्यापन के बाद, संवेदक को संगमा में कार्य बंद करने के निर्देश जारी किए (दिसंबर 2018) यद्यपि, 37 *प्रतिशत* कार्य पूर्ण हो गया था। प.का.इ., गढ़वा ने आगे संवेदक को प्लिंथ की ऊंचाई को एक मीटर तक बढ़ाने के बाद कार्य फिर से शुरू करने का निर्देश दिया (अगस्त 2019)। हालांकि, संवेदक ने प्लिंथ की ऊंचाई बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की (जुलाई 2020) क्योंकि 37 *प्रतिशत* काम पहले ही पूर्ण हो चुका था और कंपनी से अनुबंध को समाप्त करने का अनुरोध किया था। बिष्णुपुरा और डंडा का कार्य भी पूरा नहीं हुआ[27]। संवेदक द्वारा कार्य बंद करने (नवंबर 2019) के बाद कंपनी उसी ही संवेदक द्वारा

---

[24] बिष्णुपुरा, डंडा और संगमा (गढ़वा) में झा.बा.आ.वि. ।

[25] फरवरी 2018 में मुख्य मंत्री जन संवाद केंद्र में एक शिकायत में, का.अ., प.का.इ., गढ़वा द्वारा और का.अ., लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा द्वारा अक्टूबर 2018 में पुष्टि की गई थी।

[26] का.अ., लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा प.का.इ., गढ़वा ।

[27] बिष्णुपुरा (80 *प्रतिशत*) और डंडा (99 *प्रतिशत*)।

कार्य पूर्ण करने के लिए या अनुबंध समाप्त करके नई निविदा के माध्यम कार्य पूर्ण कराने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सका।

यह आगे देखा गया कि संवेदक ने जी.एस.टी. की अंतर राशि की प्रतिपूर्ति, प्रतिभूति जमा निर्गत करने और अनुबंध को समाप्त करने हेतु कंपनी द्वारा रोके गए परिनिर्धारित क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए वाणिज्यिक न्यायालय, रांची से संपर्क किया था (जुलाई 2022) और मामला न्यायालय के अधीन चला गया। नवंबर 2019 के बाद कार्य फिर से शुरू नहीं किया जा सका और इस प्रकार, झा.बा.आ.वि., डंडा और झा.बा.आ.वि., बिष्णुपुरा को आंशिक रूप से पूर्ण की गई संरचनाओं पर ₹5.60 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया, जबकि झा.बा.आ.वि., संगमा की परित्यक्त संरचना पर ₹2.80 करोड़ का अपव्यय हुआ। झा.बा.आ.वि., संगमा (गढ़वा) की परित्यक्त संरचना की **चित्र 2.1** और **2.2** में दर्शायी गई है।

चित्र 2.1	**चित्र 2.2**
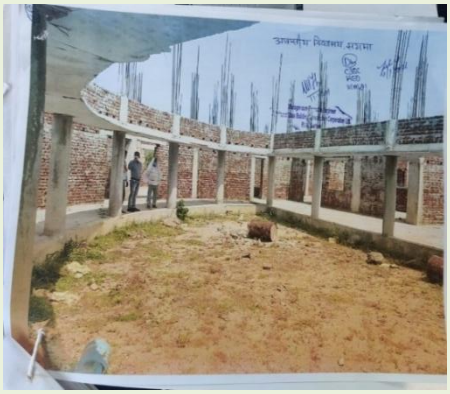	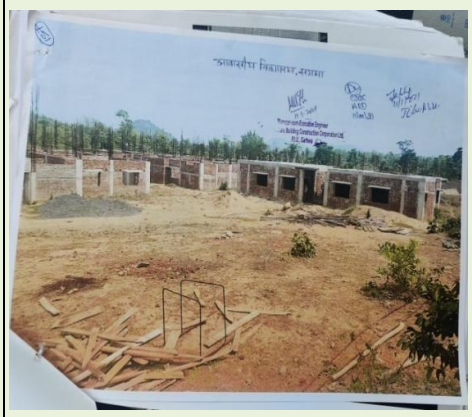

झा.बा.आ.वि., संगमा, गढ़वा के लिए निर्मित अपूर्ण और परित्यक्त भवन (11.01.2021)

इस प्रकार, वास्तविक स्थल स्थितियों के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए बिना कार्य शुरू करना, तकनीकी समिति की अनुपस्थिति में तकनीकी व्यवहार्यता का पता न लगाना और कार्य को पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई करने में कंपनी की असमर्थता के कारण ₹8.40 करोड़[28] का व्यय करने के बाद कार्य अपूर्ण रहे।

झा.बा.आ.वि., संगमा के मामले में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि संवेदक को प्लिंथ की ऊंचाई को सुरक्षित स्तर तक बढ़ाने का निर्देश दिया

[28] प्रत्येक झा.बा.आ.वि. (डंडा, बिष्णुपुरा और संगमा) पर ₹ 2.80 करोड़।

गया था, लेकिन उसने अदालत से संपर्क किया था, और शेष दो झा.बा.आ.वि. का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। आगे कहा गया कि चूंकि मामला न्यायालय मे विचाराधीन है, इसलिए कंपनी न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही कार्रवाई कर सकती है।

झा.बा.आ.वि., संगमा के मामले में उत्तर तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि कंपनी ने संवेदक द्वारा इनकार (जुलाई 2020) के बाद कार्य पूर्ण करने के लिए उचित कार्रवाई नहीं की थी।

अनुशंसा 2: कंपनी कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन हेतु तकनीकी समिति का गठन सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा, कंपनी वास्तविक स्थल स्थितियों के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन, नक्शा और रूपांकण तैयार करने के बाद ही कार्य शुरू करना सुनिश्चित कर सकती है।

2.5.3 मानव संसाधन प्रबंधन

अपने व्यवसाय के नियमों के अनुसार, कंपनी सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता होती है। कंपनी के नि.मं. को नियुक्तियों, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन के निर्धारण आदि सहित जनशक्ति भर्ती और प्रबंधन के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया था।

कंपनी की स्वीकृत मानव बल के विरुद्ध कार्यरत बल की उपलब्धता **तालिका 2.4** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4: स्वीकृत बल और कार्यरत बल (मार्च 2023)

पद	स्वीकृत बल	वास्तविक परिनियोजन	रिक्ति	अभ्युक्तियां
प्रबंध निदेशक (प्र.नि.)	01	01	0	सचिव, भ.नि.वि. को अतिरिक्त प्रभार
कार्यकारी निदेशक (का.नि.)	01	01	0	मुख्य अभियंता, भ.नि.वि.को अतिरिक्त प्रभार
महाप्रबंधक (म.प्र.)	05	02	03	अतिरिक्त प्रभार के रूप में भ.नि.वि.से प्रतिनियुक्त
उप महाप्रबंधक (उ.म.प्र.)	10	03	07	अतिरिक्त प्रभार के रूप में भ.नि.वि. से दो और आश्रित प्रभार के भीतर एक उ.म.प्र. तैनात किया गया।

मुख्य लेखा अधिकारी (मु.ले.प.)	01	01	00	-----
प्रबंधक (तकनीकी)	41	22	19	46 *प्रतिशत* की कमी
प्रबंधक (लेखा)	05	00	05	100 *प्रतिशत* की कमी
प्रबंधक (वैधानिक)	01	0	01	100 *प्रतिशत* की कमी-
प्रबंधक (प्रशासन)	01	01	00	-----
प्रबंधक (मानव संसाधन)	01	00	01	100 *प्रतिशत* की कमी
सहायक अभियंता (स.अ.)	72	09	63	88 *प्रतिशत* की कमी
कनीय अभियंता (क.अ.)	106	27	79	75 *प्रतिशत* की कमी
अन्य कर्मचारी	348	57	291	84 *प्रतिशत* की कमी
कुल	**593**	124	**469**	

(*स्रोत: झा.रा.भ.नि.नि.लि.*)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2023 तक कंपनी में कार्यरत बल की भारी कमी (79 *प्रतिशत*) थी, जिसने कम्पनी द्वारा सेवाओं को प्रदान करने के संदर्भ में इसके प्रदर्शन को प्रभावित किया जैसा कि **कंडिका 2.5.5.4** और **2.5.5.5** में वर्णित है, और निगरानी और कार्य का पर्यवेक्षण को भी प्रभावित किय। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

- प.का.इ. स्तर पर स.अ. और क.अ. के पद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्रारंभिक प्राक्कलन, कार्यों की प्रगति की नियमित अनुश्रवण, माप दर्ज करने और संवेदक के चलंत लेखा/अंतिम विपत्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, जैसा कि अभिलेखो से देखा गया है, स.अ. (88 *प्रतिशत*) और क.अ. (75 *प्रतिशत*) के पदों में अत्यधिक कमी थी।

उत्तर में**,** विभाग ने कहा **(**जुलाई 2024**)** कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा स.अ. और क.अ. की भर्ती पर रोक लगा दी गई है **(**23 मार्च 2017**)**। आगे कहा गया कि स.अ. और क.अ प्रतिनियुक्ति के आधार पर सरकारी विभागों से लिए गए हैं।

- कंपनी के गठन के संबंध में भवन निर्माण विभाग के संकल्प (24.11.2015) के अनुसार, भ.नि.वि. के प्रधान सचिव/सचिव नि.मं. के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्र.नि. एक पेशेवर होगा। हालांकि, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, प्र.नि. या तो राज्य सरकार का अधिकारी होगा जो विशेष सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा या तकनीकी या पेशेवर होगा। प्र.नि. के पास पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियां होंगी और वे

कंपनी के मामलों का प्रबंधन करेंगे इसके अलावा, जब तक कि समय-समय पर राज्यपाल द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है, प्रधान सचिव/सचिव, भ.नि.वि., झा.स., कंपनी के प्र.नि. होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि कंपनी के गठन के बाद से कोई नियमित प्र.नि. (जून 2016 से फरवरी 2018 को छोड़कर) नहीं था, और यह पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रधान सचिव/सचिव, भ.नि.वि. द्वारा धारण किया गया था। इस प्रकार, विशेष सचिव को कंपनी का प्र.नि.बनाने संबंधी खंड का एसोसिएशन के लेखों में शामिल करने के कारण, विभागीय स्तर पर कंपनी के प्रदर्शन की स्वतंत्र अनुश्रवण की कमी थी, और इसके संचालन में पूर्णकालिक प्रबंधन की अनुपस्थिति थी।

इसी तरह, उ.म.प्र. (प्रशासन) और म.प्र. (योजना और रूपांकण) के पद अभियंता प्रमुख (अ.प्र.), भ.नि.वि. द्वारा और का.नि. का पद मुख्य अभियंता (मु.अ.), भ.नि.वि. द्वारा अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण किए गये थे। इस प्रकार, क्षेत्र स्तर पर कंपनी द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की पूर्णकालिक और स्वतंत्र अनुश्रवण की कमी थी।

विभाग ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया **(**जुलाई 2024**)**।

- इसके अलावा, कंपनी के पास आंचलिक प्रबंधकों (अधीक्षण अभियंता के स्तर के) के पांच स्वीकृत पद हैं। हालांकि, आंचलिक कार्यालयों की स्थापना नहीं की गई है और अक्टूबर 2023 तक कोई आंचलिक प्रबंधक नियुक्त नहीं किये गये थे, जिसने क्षेत्र स्तर पर योजनाओं की अनुश्रवण को प्रभावित किया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2024) कि मानव बल की कमी के कारण आंचलिक कार्यालय स्थापित नहीं किए जा सके।

- कंपनी के 24 प.का.इ. के विरुध्द, 17 प.का.इ. का प्रबंधन कंपनी के अभियंताओ[29] द्वारा किया जा रहा है, जबकि सात प.का.इ.[30] के मामले में,

---

[29] प्रत्येक प.का.इ. में एक प्रबंधक (तकनीकी), दो सहायक प्रबंधक और चार कनीय प्रबंधक।

[30] गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, लातेहार, साहिबगंज, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां।

संबंधित जिलों के भ.नि.वि. के अभियंताओ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा, 17 प.का.इ. में, 17 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले पांच प्रबंधकों की कमी थी। हालांकि, इसकी तुलना में मुख्यालय स्तर पर प्रबंधकों की एक बड़ी संख्या थी, जहां स्वीकृत पदों की संख्या दो के विरुद्ध छहः प्रबंधक तैनात थे, जिससे एक एकतरफा परिनियोजन हुआ।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि प्रबंधकों को प.का.इ. में रिक्त पदों के खिलाफ तैनात किया गया है।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इन प्रबंधकों की प्रतिनियुक्ति/तैनाती आदेश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

- यह देखा गया कि कंपनी ने विभिन्न संवर्गों में 593 पदों[31] की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 144 व्यक्तियों की भर्ती के लिए टुकड़ों में 12 विज्ञापन (2016-17 और 2022-23 के बीच) प्रकाशित किए थे (प्रत्येक विज्ञापन में 03 से 42 पदों तक)। इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने, अदालती मामलों, उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसे कारणों से 144 में से केवल 72 व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सका। इसके अलावा, 63 स.अ. और 79 क.अ. की कमी को पूरा करने के लिए, 2016-17 में 14 अभियंताओ (छह स.अ. और आठ क.अ.) के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के के कारण कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि चल रही परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में अभियंताओ की आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर भर्ती अधिसूचना जारी की गई थी।

उपरोक्त विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कंपनी बड़ी संख्या में कार्यों के भार के बावजूद मानव बल की तीव्र कमी का सामना कर रही है। कर्मचारियों की कमी, परियोजनाओं के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और

[31] कंपनी द्वारा भर्ती नोटिस प्रकाशित होने की तारीखों पर वास्तविक रिक्तियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

अनुश्रवण के कारणों में से एक थी, जिसके कारण कार्य या तो विलम्ब से पूर्ण हुए या अपूर्ण रहे।

2.5.4 परियोजनाओं का निष्पादन

कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से 1,328 कार्यों को शुरू किया था, जिनमें से मार्च 2023 तक 79 कार्यों को छोड़ दिया गया था; 33 कार्यों को रोक किया गया था; 726 कार्य पूर्ण हो चुके थे; 218 कार्य प्रगति पर थे और 272 कार्य प्रारंभिक चरणों में थे (अर्थात निविदा में, वि.प.प्र. स्तर पर और प्र.अ. स्तर में)। लेखापरीक्षा ने 206 कार्यों[32] की जांच की और अनुबंध प्रबंध, व्यय प्रबंध, गुणवत्ता प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण में अनियमितताओं के मामलों को देखा, जैसा कि आगे की कंडिकाओ में चर्चा की गई है।

2.5.4.1 अनुबंध प्रबंध

झा.लो.नि.वि. कोड के नियम 158 (सी) के अनुसार, विभाग निविदा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ई-प्रोक्योरमेंट, ई-टेंडर जैसी प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपना सकता है। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने अनुबंध प्रबंधन में निम्नलिखित अनियमितताओं को देखा।

बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय का प्रावधान

झा.लो.नि.वि. संहिता के नियम 159 (ए) के अनुसार, सीलबंद निविदाओं को अनिवार्य रूप से सबसे खुले और सार्वजनिक तरीके से, इंटरनेट पर, समाचार पत्रों में और सार्वजनिक नोटिस के द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किया जाना था। ₹2.50 लाख से अधिक मूल्य के किसी भी कार्य के लिए, समाचार पत्रों में और इंटरनेट पर निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.)/कोटेशन का प्रकाशन अनिवार्य था। इसके अलावा, वेबसाइट पर निविदा के प्रकाशन के बाद, बोलियां जमा करने के लिए अनुमत समय भी झा.लो.नि.वि. संहिता में निर्धारित किया गया है।

---

[32] छोड़े गए कार्य: 79, रुके हुए कार्य: 33, पूर्ण कार्य: 68 और प्रगति पर कार्य: 26

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित 94 कार्यों में से 56 में,जिनकी निविदा/उद्धरण राशि ₹79 लाख और ₹426.11 करोड़ के बीच थी, बोलियां प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय झा.लो.नि.वि. संहिता में निर्धारित समय से कम था, जैसा कि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: बोलियां जमा करने के लिए अनुमत समय

निविदा/कोटेशन राशि।	कार्यों की संख्या	प्रत्येक मामले में झा.लो.नि.वि.के अनुसार निर्धारित समय (दिनों में)	समय (दिनों में) अनुमत
₹2.50 लाख से अधिक और ₹2.50 करोड़ तक	02	14	9-10
₹2.50 करोड़ से अधिक और ₹20 करोड़ तक	40	21	9-17
₹20 करोड़ से अधिक और ₹50 करोड़ तक	05	21.	10-15
₹50 करोड़ से अधिक	09	28	11-17
कुल	**56**		

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 56 नमूना-जांचित कार्यों में बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय निर्धारित समय से कम था ***(परिशिष्ट 2.2)***। निर्धारित बोली अवधि कम होने के कारण, सभी संभावित बोलीदाताओं की भागीदारी सीमित हो सकती थी, जो संभावित रूप से प्राप्त दरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि कार्य की तात्कालिकता के कारण, बोलियां प्रस्तुत करने के लिए कम समय दिया गया था। आगे कहा गया कि आगामी निविदाओं में इसका पालन किया जाएगा।

उत्तर ठोस नहीं है क्योंकि निविदा फाइलों में कार्य की तात्कालिकता के बारे में कोई औचित्य दर्ज नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कंपनी में कोई औचित्य दिए बिना लगभग सभी कार्यों के लिए लघु निविदा नोटिस जारी करने की प्रथा प्रचलित थी।

पारदर्शिता की कमी

झा.लो.नि.वि. संहिता के नियम 163 (नोट 3) के अनुसार, दो-लिफाफा बोली प्रणाली में, यदि सबसे कम दर एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत की जाती है, तो विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार, तकनीकी मूल्यांकन में बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर कार्य प्रदान किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में, बोलीदाताओं का मूल्यांकन विभिन्न मापदंडों जैसे क्रेडिट सुविधा, कुल कारोबार, कार्य अनुभव, बोली क्षमता, पंजीकरण की तारीख आदि के आधार पर किया जाता है। विभाग को बोलीदाताओं की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए इन मापदंडों के अनुसार चिह्नित करना आवश्यक है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने किसी भी दिशानिर्देश के अभाव में तकनीकी मूल्यांकन के दौरान बोलीदाताओं के चिन्हित/मूल्यांकन करने की पद्धति को नहीं अपनाया। फलस्वरूप, कार्यों को आवंटित करने में एकरूपता की कमी के मामले सामने आये जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

- चार कार्यों[33] में, यह पाया गया कि एक से अधिक न्यूनतम बोलीदाता थे। जबकि एक मामले[34] में अधिकतम अनुभव वाले बोलीदाता को कार्य आवंटित किया गया था (जनवरी 2018), अन्य तीन मामलों में, कंपनी द्वारा कम कार्य अनुभव वाले तीन बोलीदाता को कार्य आवंटित किए गए थे (जनवरी 2018 और मार्च 2019 के बीच)।

- मानक बोली दस्तावेज (मा.बो.द.) एक अनुबंध दस्तावेज है, जो नवंबर 2007 में पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किया गया था और यह ₹2.50 करोड़ से अधिक के सभी कार्य अनुबंधों के लिए सभी लोक निर्माण विभागों पर लागू होता है। मा.बो.द. के खंड 4.5 ए (सी) के अनुसार, बोलीदाताओं को तकनीकी बोली के साथ एक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान निष्पादित सीमेंट कंक्रीट और मिट्टी कार्य की मात्रा का विवरण हो, प्रस्तुत करना था, और तकनीकी मूल्यांकन समिति

---

[33] खाद्य शिल्प संस्थान, देवघर का निर्माण; डिग्री कॉलेज, महेशपुर, पाकुड़; का निर्माण नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, दुमका का निर्माण और आई.टी.आई., महगामा, गोड्डा का निर्माण।

[34] खाद्य शिल्प संस्थान, देवघर का निर्माण।

को पिछले पांच वर्षों में से किसी एक में निष्पादित कार्य के उच्चतम मूल्य पर विचार करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि कंपनी ने एक कार्य[35] के लिए तकनीकी मूल्यांकन के दौरान एक बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया (अगस्त 2017) क्योंकि तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र[36], को वार्षिक रूप से विभाजित नहीं किया गया था। हालांकि, एक अन्य कार्य[37] के लिए कंपनी ने एक बोलीदाता को इस तथ्य के बावजूद कि कार्य अनुभव का वर्ष-वार विभाजन[38] प्रस्तुत नहीं किया गया था, तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया (जनवरी 2018) और उसे कार्य भी आवंटित किया (जनवरी 2018) ।

इस प्रकार, किसी भी दिशानिर्देश के अभाव में, कंपनी ने तकनीकी मूल्यांकन के दौरान बोलीदाताओं को चिन्हित करने/मूल्यांकन के लिए एक समान मानक लागू नहीं किए और किसी भी सुसंगत मानदंडों का पालन किए बिना कार्यों को आवंटित किया। इससे कार्यों के आवंटन में गैर-पारदर्शिता का जोखिम भी बढ़ गया और संवेदकों को अनुचित लाभ देने की संभावना भी बढ़ गयी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि भविष्य की निविदाओं में तकनीकी मूल्यांकन के समय बोलीदाताओं को चिन्हित करने /मूल्यांकन करने के नियम का पालन किया जाएगा।

अपर्याप्त बोली मूल्यांकन

- ***अपर्याप्त बोली क्षमता***

मा.बो.द. के खंड 4.7 के अनुसार, न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता केवल तभी योग्य होंगे जब उनकी उपलब्ध बोली क्षमता कुल बोली मूल्य से अधिक हो। इसके अलावा, निर्धारित बोली क्षमता की गणना

---

35 पीरटांड, गिरिडीह में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण।

36 17 फरवरी 2015 से 12 जून 2016 की अवधि के लिए कार्य अनुभव दिया गया था।

37 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, लातेहार का निर्माण।

38 12 मार्च 2012 से 16 जनवरी 2014 की अवधि के लिए कार्य अनुभव दिया गया था

मा.बो.द. में निर्धारित सूत्र[39] के अनुसार की जानी थी। बोलीदाता जिन वर्तमान प्रतिबद्धताओं और चालू कार्यों में भाग ले रहा था, उनका विवरण, सूचीबद्ध प्रत्येक कार्य के लिए पूरा होने की निर्धारित अवधि के साथ, संबंधित अभियंता-प्रभारी/कार्यपालक अभियंता/नियोक्ता द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना था।

इस संदर्भ में, नमूना-जांचित 94 कार्यों में से 20 ***(परिशिष्ट 2.3)*** के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि बोलीदाताओं ने निविदा के दौरान अपनी बोलियों के साथ पिछले पांच वर्षों का लाभ और हानि (पी/एल.) खाता प्रस्तुत किया था। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, कंपनी ने निर्धारित बोली क्षमता का निर्धारण करने के लिए नागरिक अभियांत्रिकी कार्यों के अधिकतम मूल्य के रूप में बोलीदाताओं के वार्षिक खातों से प्राप्त संचालन से अनुबंध कार्यों / राजस्व से सकल प्राप्तियों के मूल्य पर विचार करके बोली लगाने वाला को योग्य घोषित किया। हालांकि, पी/एल खातों ने इसे स्पष्ट नहीं किया/या निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया कि प्राप्तियां विशेष रूप से नागरिक निर्माण कार्यों से ही थीं। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि मौजूदा प्रतिबद्धता और चालू कार्यों के विवरण, साथ ही बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत पूर्णता की निर्धारित अवधि, प्रभारी अभियंता/कार्यपालक अभियंता/नियोक्ता द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित नहीं थी। इस प्रकार, इन मामलों में कंपनी द्वारा बोलीदाताओं की निर्धारित बोली क्षमता की गणना गलत थी। इन 20 बोलीदाताओं का चयन जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे और जिनके पास नागरिक कार्य के निष्पादन का पर्याप्त अनुभव नहीं था, परियोजनाओं की धीमी प्रगति और समय पर पूर्ण नही होने का एक कारण था, जैसा कि ***कंडिका 2.5.5.10*** में चर्चा की गई है।

---

[39] (ए*एन*2-बी) जहां "ए" पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में निष्पादित सिविल इंजीनियरिंग कार्यों का अधिकतम मूल्य है; "एन" उस कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या है जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थी; और "बी" अगले ...../12 वर्षों के दौरान पूरी की जाने वाली मौजूदा प्रतिबद्धताओं और चल रहे कार्यों का मूल्य है (उन कार्यों के पूरा होने की अवधि जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि भविष्य की निविदाओं में मा.बो.द. के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

- ***उपकरण और प्रमुख कर्मियों के बारे में अधूरी जानकारी प्रस्तुत करना***

मा.बो.द. के खंड 4.5 बी के अनुसार, प्रत्येक बोलीदाता को (क) संयंत्र/उपकरण की संख्या, प्रकार और क्षमताओं के साथ कार्य के लिए प्रमुख और महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार प्रत्येक संचालन के लिए पांच साल के समय चक्र को ध्यान मे रखते हुए उत्पादन क्षमता ,और (ख) पर्याप्त अनुभव वाले कर्मियों की उपलब्धता प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी ।

चार कार्यों ***(परिशिष्ट 2.4)*** में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन कार्यों की तकनीकी बोलियों में बोलीदाताओं द्वारा प्रमुख कर्मियों की योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र और आयु के साथ उपकरणों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। एक[40] कार्य के मामले में यह देखा गया कि उपकरण की आयु पांच साल की निर्धारित सीमा से अधिक थी। हालांकि, तकनीकी मूल्यांकन चरण में अपर्याप्त/अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित करने के बजाय, तैनात कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्र और उपकरण और संयंत्र की आयु के वास्तविक सत्यापन के बिना कंपनी ने सभी चार बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया और उन्हें कार्य आवंटित किया। योग्य कर्मी और आवश्यक उपकरणों की कमी कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों में से एक थी, क्योंकि सभी चार कार्य निर्धारित पूर्णता तिथि से 21 से 31 महीने बीत जाने के बाद 15 से 71 प्रतिशत के बीच भौतिक प्रगति के साथ अपूर्ण थे (अक्टूबर 2023 तक)।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि भविष्य की निविदाओं में इसका पालन किया जाएगा।

अनुबंध के निष्पादन में विलम्ब

[40] दुमका में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण।

मा.बो.द. के खंड 33 के अनुसार, अनुबंध पर नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं और इस स्वीकृति पत्र के साथ कार्य आवंटन की अधिसूचना के 28 दिनों के अंदर सफल बोलीदाता को भेजा जाना है, और सफल बोलीदाता के द्वारा इसके प्राप्ति के 21 दिनों के अंदर अनुबंध पर हस्ताक्षर करके इसे नियोक्ता को समर्पित करना है। इसके अलावा, मा.बो.द. के अनुबंध डेटा के खंड 5 के अनुसार, कार्य को प्रारंभ करने सम्बंधी सूचना की तिथि ही कार्यारम्भ तिथि होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने किसी भी कार्य के लिए कार्य को प्रारंभ करने सम्बंधी सूचना निर्गत नहीं किया था और अनुबंध की तारीख को कार्य शुरू करने की तारीख के रूप में माना था जो कि मा.बो.द. के प्रावधान का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सफल बोलीदाताओं को कार्य आवंटित करने के बाद 35 कार्यों के अनुबंधो पर हस्ताक्षर करने में 49 दिनों की निर्धारित अधिकतम समय सीमा के विपरित विलम्ब (एक और 466 दिनों के बीच) हुआ ***(परिशिष्ट 2.5)***। अनुबंधो के निष्पादन में विलम्ब के कारण कार्य प्रारम्भ करने और पूर्ण होने मे विलम्ब हुआ।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया **(**जुलाई 2024**)** और कहा कि प.का.इ. को भविष्य में मा.बो.द. के प्रावधानों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुबंध प्रबंध में अन्य रोचक बिंदु

- **अनियमित भुगतान**

नए वैक्सीन उत्पादन केंद्र, पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान, कांके, रांची के लिए उपकरणों के निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, अधिष्ठापन और परीक्षण (टर्नकी आधार पर) के लिए फर्मों/कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित (मार्च 2014) की गईं। जुलाई 2014 में, एक संवेदक ने कार्यपालक अभियंता, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के साथ ₹27.95 करोड़ मूल्य का एक एफ-2[41] अनुबंध किया और कार्य के निष्पादन के दौरान

[41] झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित कार्यों के टर्नकी अनुबंध के लिए संविदा का एक प्रारुप (एफ -2)

पालन किए जाने वाले अनुबंध के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर किया। एफ-2 अनुबंध के नियमों और शर्तों में निर्माण सामग्री और श्रम की कीमत में किसी भी वृद्धि के लिए मूल्य समायोजन के भुगतान का प्रावधान नहीं था। इस कार्य का कार्यान्वयन कंपनी के गठन के बाद उसे स्थानांतरित कर दिया गया (नवंबर 2015)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि के लिए जुलाई 2014 से दिसंबर 2019 तक की अवधि के लिए संवेदक को ₹1.32करोड़ के मूल्य समायोजन का भुगतान किया था (फरवरी 2021)। यह भी देखा गया कि संवेदक ने कंपनी से मूल्य समायोजन प्राप्त करने के लिए मा.बो.द. अनुबंध की एक प्रति प्रस्तुत की थी जिसपर नियोक्ता (कंपनी या का.अ., पशुपालन और मत्स्य विभाग) द्वारा हस्ताक्षर नही किया गया था, जबकि यह आवश्यक था। इस प्रकार, मूल्य समायोजन का भुगतान कंपनी द्वारा अमान्य दस्तावेजों के आधार पर संवेदक को किया गया था और इसलिए यह अनियमित था।

विभाग ने कहा **(**जुलाई 2024**)** कि मूल्य समायोजन का भुगतान मा.बो.द. की शर्तो के अनुसार किया गया था।

उत्तर तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग द्वारा अनुबंध को एफ-2 समझौते के प्रारूप में निष्पादित किया गया था**,** जिसमें अनुबंध मूल्य और पूर्णता अवधि के बावजूद मूल्य समायोजन के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा**,** मा.बो.द. प्रारूप पर निष्पादित कोई भी अनुबंध अभिलेख मे नहीं था और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद**,** केवल संवेदक द्वारा हस्ताक्षरित मा.बो.द. अनुबंध की एक प्रति कंपनी द्वारा ₹1.32 करोड़ के मूल्य समायोजन के भुगतान के लिए स्वीकार की गई थी।

- **अनुपूरक अनुबंध में अनियमितताएं**

झा.लो.नि.वि. संहिता (नियम-182) में कहा गया है कि बिल ऑफ क्वांटिटीज (बी.ओ.क्यू.) में शामिल नहीं किए गए कार्य की मदों को

अतिरिक्त मद[42] कहा जाता है और ऐसी मदों के लिए हमेशा एक अनुपूरक अनुबंध (अ.अ.) निष्पादित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक परियोजना के मूल्य अनुबंध के अन्तर्गत शामिल न किये गये कार्य के दायरे में कोई भी परिवर्तन, जिसे कार्य प्रगति पर होने के दौरान आवश्यक समझा जाता है, उसे अनुपूरक प्राक्कलन द्वारा आच्छादित किया जाना चाहिए, जिसकी कुल राशि प्र.अ. की अनुमेय सीमा तक सीमित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सितंबर 2016 और अगस्त 2019 के बीच आवंटित किये गये पांच कार्यों[43] में ₹33.33 करोड़ की लागत से दो से 16 अतिरिक्त कार्यों की मदों को मंजूरी दी गयी थी (जून 2021 और जनवरी 2023 के बीच) जिसके लिए अनुपूरक अनुबंध (अ.अ.) निष्पादित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये मदें बी.ओ.क्यू. का हिस्सा नहीं थे। हालांकि, कंपनी ने उक्त अनुपूरक अनुबंध को निष्पादित नहीं किया और संवेदकों को ₹33.33 करोड़ का अनधिकृत भुगतान किया।

इसके अलावा, एक अन्य कार्य[44] में, नक्शा में परिवर्तन के कारण बी.ओ.क्यू. में कार्यों की कुछ मदों की मात्रा बढ़ गई थी। एक अनुपूरक प्राक्कलन तैयार करने के विपरित, कंपनी द्वारा विचलन के लिए ₹59.10 लाख का अनुपूरक अनुबंध निष्पादित किया गया (जून 2020) और संवेदक को कार्य पूर्ण करने के लिए चार महीने की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी गई थी।

उत्तर में**,** विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया **(**जुलाई 2024**)** और कहा कि इसे चालू परियोजनाओं में सुधारा जाएगा।

- **बीमा द्वारा आच्छादित नहीं किए गए कार्य**

मा.बो.द. के अनुबंध की शर्तों के खंड 13 के अनुसार, संवेदकों को कार्य के प्रारम्भ की तारीख से दोष देयता अवधि के अंत तक बीमा करना था, ताकि

---

[42] अतिरिक्त मदों की दरें कार्य के निष्पादन के दौरान वर्तमान एस.ओ.आर. की दर पर आधारित होंगी।

[43] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय गढ़वा; डिग्री कॉलेज, छतरपुर (पलामू) और हजारीबाग, दुमका और पलामू में तीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण।

[44] महेशपुर, पाकुड़ में डिग्री कॉलेज का निर्माण ।

कार्यों, संयंत्र और मशीनरी, उपकरणों, और अनुबंध के संबंध में व्यक्तिगत चोट या मौत आदि के किसी भी नुकसान या क्षति से बचाव किया जा सके। इसके अलावा, यदि संवेदक आवश्यक बीमा प्रदान करने में विफल रहा, तो नियोक्ता (कंपनी) को संवेदक को देय किसी भी भुगतान से बीमा के प्रीमियम की वसूली करनी थी।

कंपनी द्वारा निष्पादित कार्यों के अभिलेखो की जांच (नवंबर 2015 से अक्टूबर 2023) से पता चला कि नमूना-जांचित 94 कार्यों में से 93[45] के मामले में, संवेदकों ने बीमा कराने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, कंपनी ने इन 93 कार्यों में संवेदकों को देय भुगतान से बीमा प्रीमियम भी वसूल नहीं किया था।

उत्तर में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि आगामी कार्यों में बीमा कराने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

- **प्रतिधारण राशि**

मा.बो.द. और अनुबंध डेटा के खंड 48 के अनुसार, नियोक्ता द्वारा अंतिम अनुबंध मूल्य के अधिकतम आठ *प्रतिशत* के अधीन संवेदकों को भुगतेय प्रत्येक विपत्र का नौ प्रतिशत प्रतिधारण राशि[46] के रूप में रोककर रखना था जब तक कि कार्य पूर्ण न हो जाये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित कार्यों में, कंपनी ने संवेदकों को निर्गत भुगतान से निर्धारित नौ प्रतिशत के स्थान पर केवल आठ प्रतिशत रोककर रखा था। इस प्रकार, संवेदकों द्वारा कार्य छोड़ देने, कार्य निष्पादन में त्रुटि आदि के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को पूरी तरह से आच्छादित नहीं किया गया था।

उत्तर में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि मा.बो.द. के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

---

45 एक काम के लिए बीमा की आवश्यकता नहीं थी।

46 प्रतिधारण राशि एक ग्राहक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए रोका जाता है कि संवेदक आवश्यक मानकों के अनुसार एक परियोजना को पूरा करे और देयता अवधि के दौरान कार्य मे आई सभी त्रुटियों का सुधार करे।

अनुशंसा 3: कंपनी सबसे प्रतिस्पर्धी कीमतों को आकर्षित करने के लिए एक पारदर्शी और समान बोली प्रणाली स्थापित और लागू कर सकती है। यह संवेदकों के साथ हस्ताक्षरित अनुबंधों के नियमों और शर्तों का पालन भी सुनिश्चित कर सकती है।

2.5.5 व्यय प्रबंध

झारखंड वित्तीय नियमों के नियम 9 में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक निधि से व्यय करने या व्यय अधिकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। इसके अलावा, नियम 10 में कहा गया है कि विभाग का प्रत्येक प्रमुख, विभाग में हर कदम पर वित्तीय व्यवस्था और सख्त मितव्ययता को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा ने कार्यो के बीच में छोड़ देने और बंद करने के कारण अप्व्यय और निष्फल व्यय के उदाहरणों का अवलोकन किया। इसके अलावा, मा.बो.द. के निर्धारित मानदंडों का पालन न करने, अतिरिक्त भुगतान के मामलों, सरकारी बकाया राशि की वसूली न करने आदि जैसे मामले भी पाये गये, जैसा कि आगे कि कंडिकओं में चर्चा की गई।

2.5.5.1 संवेदकों को अत्यधिक भुगतान

- मा.बो.द. में 12 महीने से अधिक की पूर्णता अवधि वाले कार्य अनुबंधों में मूल्य समायोजन (मू.स.) का प्रावधान शामिल है। ऐसे अनुबंधों में, संवेदक संबंधित अभियंता को किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य का मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा और मू.स. प्रत्येक महीने के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, श्रम घटक के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा और निर्माण सामग्री घटक के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्माण सामग्री और श्रम के मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। निविदा खोलने की तिथि से 28 दिन पहले के महीने के आधार सूचकांक पर मा.बो.द. के अनुबंध आंकड़ों में प्रदान किए गए सूत्र के आधार पर, मूल्य समायोजन की गणना के लिए विचार किया जाना था।

झा.लो.नि. लेखा संहिता के नियम 247 के साथ पठित नियम 243 के अनुसार, क.अ. को एक संवेदक का विपत्र तैयार करने से पहले मापी पुस्तिका (मा.पु.) में किए गए कार्य के विवरण और मात्रा दर्ज करना था। किए गए कार्य के लिए भुगतान आमतौर पर मासिक रूप से चालू लेखा (चा.ले.) विपत्र पर किया जाना था।

सात कार्यों[47] में, संवेदकों ने किए गए कार्यों के अनुमानित मूल्य के मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे और प.का.इ. के अभियंताओ ने मा.पु. में निष्पादित कार्यों की मात्रा की मासिक अभिलेखबद्धता सुनिश्चित नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प.का.इ. के प्रबंधकों ने मासिक आधार पर मू.स. का निर्धारण नहीं किया था क्योंकि कार्यों को लगातार दो चा.वि. के बीच एक महीने से अधिक के अंतराल के साथ मापा गया था। इसके अलावा, एक[48] मामले में, कंपनी ने ईंटों के स्थान पर अपवर्तनीय उत्पादों का एक अस्वीकार्य सूचकांक और एक गलत आधार सूचकांक लागू किया था ।मासिक आधार पर किए गए कार्य के मूल्य की अभिलेखबद्धता के अभाव में, लेखापरीक्षा ने दो लगातार चा.वि. के बीच के दिनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, किए गए कार्य के औसत मूल्य को लेकर लागू मू.स. की गणना की, और पाया कि सात कार्यों में ₹1.76 करोड़ का मू.स. वसूलनीय था ***(परिशिष्ट 2.6)***।

उत्तर में**,** विभाग **(**जुलाई 2024**)** ने कहा कि मूल्य समायोजन की गणना को फिर से जांचा जाएगा**,** और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

- कंपनी द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, टुंडी, धनबाद के निर्माण के लिए ₹16.23 करोड़ मूल्य का एक अनुबंध निष्पादित किया गया था (जुलाई 2019)। अनुबंध को अंतिम रूप देने से पहले बातचीत की प्रक्रिया (जून 2019) के दौरान, संवेदक ने ₹16.27 करोड़ की उद्धृत दर पर

---

47 हजारीबाग और पलामू में मेडिकल कॉलेजों में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण और रांची में 500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल के शेष कार्य का निर्माण, 2) पी.एम.सी., धनबाद में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का निर्माण (3) गुमला में पेलेटेड पोल्ट्री फीड फार्म का निर्माण (4) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देवघर का निर्माण और (5) डिग्री कॉलेज, खिजरी, रांची का निर्माण।

48 रांची में 500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल के शेष कार्य का निर्माण।

0.25 प्रतिशत (₹4.07 लाख) की छूट की अनुमति दी थी और यह अनुबंध में परिलक्षित हुआ था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने संवेदक को किए गए (दिसंबर 2019 और जून 2023 के बीच) भुगतान (₹16.64 करोड़) से ₹4.60 लाख की उक्त छूट की कटौती नहीं की थी। फलस्वरूप, संवेदक को ₹4.60 लाख का अधिक भुगतान किया गया जो वसूलनीय था।

उत्तर में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि संवेदक से वसूली की जाएगी।

इस प्रकार, सही सूचकांकों के प्रयोग को सुनिश्चित करने में कंपनी की अक्षमता, मूल्य समायोजन की गणना के लिए विपत्रो हर महीने तैयार नही किया जाना और अनुबंधो के नियमों और शर्तों के संदर्भ के बिना विपत्रो के भुगतान के कारण ₹1.80 करोड़ का अत्यधिक भुगतान हुआ।

2.5.5.2 अत्यधिक अनुमान और उसका भुगतान

कंपनी द्वारा ₹15.77 करोड़ की लागत से 27 डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए एक मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया था (नवंबर 2016)। मॉडल प्राक्कलन के आधार पर, उपयोगकर्ता विभाग (उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास) ने (फरवरी 2017 और अगस्त 2018 के बीच) ₹425.79 करोड़ (प्रत्येक डिग्री कॉलेज के लिए ₹15.77 करोड़) के लिए प्र.अ. प्रदान किया। अनुबंधों के निष्पादन की तारीख से 24 महीने के भीतर कार्यों को पूर्ण करने के लिए संवेदकों के साथ ₹382.14 करोड़ के अनुबंध (सितंबर 2017 और जनवरी 2020 के बीच) निष्पादित किए गए थे। नमूना-जांचित 13 डिग्री कॉलेजों के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित तथ्य सामने आएः

- जबकि अनुसूचित वस्तुओं की दरें झारखंड अनुसूचित दर (जे.एस.आर.)/दिल्ली अनुसूचित दर (डी.एस.आर.) से ली गई थीं, अनुमोदित बी.ओ.क्यू. में 18 गैर-अनुसूचित मदें शामिल थीं जिनके लिए कोटेशन के माध्यम से बाजार से दरें ली गई थीं। 18 गैर-अनुसूचित मदों में से, 12 मदों की दरों में मूल्य वर्धित कर (मु.व.क.) / माल और सेवा कर

(जी.एस.टी.) शामिल थे। हालांकि, कंपनी ने बी.ओ.क्यू. तैयार करने के दौरान अनुसूचित/गैर-अनुसूचित दोनों मदों के लिए 12 *प्रतिशत* जी.एस.टी. जोड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप नमूना-जांचित 13 कार्यों में से दो (छतरपुर और महेशपुर) के बी.ओ.क्यू. में ₹9.09 लाख का अधिक आकलन हुआ। इस प्रकार, बी.ओ.क्यू. बनाने के दौरान यथोचित परिश्रम करने में कंपनी की अक्षमता के कारण लागत अनुमान में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हुआ।

- कंपनी द्वारा डिग्री कॉलेज भवनों के लिए तैयार किये गये प्राक्कलन में भूतल के साथ दो मंजिल के लिए प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, कॉलेज की इमारतों के लिए केवल तीन विराम (कुल ऊंचाई: 7.62 मीटर) के साथ दो यात्री लिफ्ट की आवश्यकता थी, लेकिन इसके खिलाफ, ₹25 लाख की दर से छह विराम (कुल ऊंचाई: 19.50 मीटर) के साथ दो यात्री लिफ्ट का प्रावधान किया गया था। कंपनी ने एक कार्य (डिग्री कॉलेज, शिकारीपारा, दुमका) के मामले में इस मद की उद्धृत दर का 40 *प्रतिशत* काट लिया (सितंबर 2023)। हालांकि, नमूना-जांचित 13 कार्यों (प्रत्येक डिग्री कॉलेज में ₹20 लाख) के प्राक्कलनो में कुल मिलाकर ₹2.60 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान था। इस प्रकार, नमूना-जांचित 11 कार्यों में इस मद में संवेदकों को ₹2.15 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। एक कार्य (डिग्री कॉलेज, महगामा, गोड्डा में) में, लिफ्टों के लिए भुगतान रोक दिया गया था (जनवरी 2023)।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि बी.ओ.क्यू. में, क्रम संख्या 121 और 181 (i) (मद 1) पर दो गैर-अनुसूचित मदों[49] के लिए, तीन इकाइयों के लिए ₹60,640 (क्रम संख्या 121 के लिए ₹1,05,000 और ₹44,360) प्रति इकाई अलग-अलग दरें, अर्थात बी.ओ.क्यू. में ₹1.82 लाख दिए गए थे, हालांकि दोनों मदें समान थे। इसी तरह, अन्य दो समान गैर-अनुसूचित मदों[50] के लिए क्रम संख्या 122 और 181(ii) (मद 2) पर, ₹4.60 लाख

[49] 200 ए स्विच, 300 ए एल्यूमीनियम बस बार, संकेत लैंप आदि का निर्माण और संयोजन

[50] 600 ए एम.सी.सी.बी., टी.पी.एन. एल्यूमीनियम बस बार, बेक लाइट इंसुलेटर आदि का निर्माण एवं संयोजन

(₹6.30 लाख/इकाई और ₹1.70 लाख / इकाई) की अलग-अलग दरें एक इकाई के लिए दिया गया था। चूंकि ये मद समान थे, इसलिए प्रत्येक डिग्री कॉलेज के बी.ओ.क्यू. में ₹6.42 लाख[51] का अतिरिक्त प्राक्कलन था और परिणामस्वरूप नमूना-जांचित 13 डिग्री कॉलेजों में ₹83.46 लाख का अतिरिक्त प्राक्कलन था। इस प्रकार कंपनी ने नमूना-जांचित नौ कार्यों में इन विभिन्न बी.ओ.क्यू. दरों पर दोनों मदों के लिए संवेदक को ₹53.61 लाख[52] का अतिरिक्त भुगतान किया था।

- राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (अक्टूबर 2020) में निर्धारित किया गया था कि श्रम और रोजगार विभाग, झा.स. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित श्रम दर का उपयोग झारखंड दरों की अनुसूची (जे.एस.आर.) तैयार करने के लिए किया जाना था। इसके अलावा, झा.लो.नि.वि. संहिता के नियम 103 के अनुसार, किसी कार्य में आवश्यक गैर-अनुसूचित वस्तुओं की दरों को डी.जी.एस. और डी. दरों से अपनाया जाना था। यदि डी.जी.एस. और डी. दरें उपलब्ध नहीं थीं, तो संबंधित क्षेत्र पर लागू केंद्र सरकार का एस.ओ.आर. को अपनाया जाना था। ऐसे मामलों में जहां कार्य के लिए आवश्यक गैर-अनुसूचित वस्तुओं की दरें, न तो डी.जी.एस. और डी. में उपलब्ध हैं न ही संबंधित क्षेत्र मे लागू भारत सरकार एस.ओ.आर. में उपलब्ध हैं, उन्हें बाजार से कोटेशन आमंत्रित करके निर्धारित की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार करने के दौरान दिल्ली की दरों की अनुसूची (डी.एस.आर.) से 25 मदों की दरों को अपनाया था क्योंकि इन वस्तुओं की दरें जे.एस.आर. में उपलब्ध नहीं थीं। हालांकि, डी.एस.आर. की दरें दिल्ली में लागू श्रम की दर के आधार पर तैयार की जाती हैं, जो झारखंड की तुलना में अधिक थी। तुलनात्मक रूप से यह देखा गया कि ऊर्जा विभाग, झा.स. और सी.पी.डब्ल्यू.डी., भारत सरकार (झारखंड राज्य में स्थित) ने डी.एस.आर. दरों को अपनाते हुए, प्रचलित स्थानीय श्रम दरों के आधार पर दरों में आवश्यक परिवर्तन किए थे।

---

[51] मद 1: ₹1.82 लाख और मद 2: ₹4.60 लाख।

[52] शेष चार नमून-जांचित कार्यों (छतरपुर, गोमिया, महागामा और शिकारीपारा में डिग्री कॉलेज) में, इन मदों के लिये कोई भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने झारखंड की श्रम दरों को अपनाकर इन 25 मदों की दरों का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि तैयार किए गए प्राक्कलनो में ₹11.99 लाख[53] ***(परिशिष्ट 2.7)*** का अधिक अनुमान था। इस प्रकार, प्रत्येक डिग्री कॉलेज की कुल सिविल निर्माण लागत मॉडल प्राक्कलन में प्रावधान किए गए ₹14.35 करोड़ के विपरित वास्तव में ₹14.23 करोड़ थी। इस प्रकार, नमूना-जांचित 13 कार्यों के लिए कार्य का आधार मूल्य बढ़ा कर बताया गया था।

उत्तर में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि संवेदकों से वसूली की जाएगी। डी.एस.आर. दरों को अपनाने के मामले में, विभाग ने कहा कि इस मुद्दे पर दर समिति की अनुसूची और उसके अनुसार की गई कार्रवाई के साथ चर्चा की जाएगी।

अनुशंसा 4: कंपनी परियोजनाओं के प्राक्कलन तैयार करने में सम्यक उद्यम सुनिश्चित कर सकती है।

2.5.5.3 अपव्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹12.42 करोड़ का व्यय करने के बाद दो कार्यों[54] को बीच में छोड़ दिया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

- झा.स. ने आगामी चुनौतियों जैसे आतंकवाद, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध आदि से निपटने के लिए राज्य पुलिस, केंद्रीय पुलिस आदि को कुशल, प्रशिक्षित और पेशेवर जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय (झा.र.श.वि.)[55] की स्थापना की (नवंबर 2016)। तदनुसार, उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग द्वारा खूंटी जिले में झा.र.श.वि. के लिए एक स्थायी परिसर के निर्माण हेतु ₹206.54 करोड़ की राशि के लिए प्र.अ. प्रदान किया गया था (नवंबर 2017)। निर्माण कार्य को दो चरणों में निष्पादित किया जाना था अर्थात

---

[53] 25 मदों का परियोजना प्राक्कलन: केवल श्रम घटक के लिए ₹1.47 करोड़ (डी.एस.आर. के अनुसार) और ₹1.35 करोड़ (जे.एस.आर. के अनुसार) ।

[54] 1) झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, खूंटी के लिए भवन का निर्माण और (2) रजरप्पा (रामगढ़) पर्यटन क्षेत्र के पूर्ण पर्यटन विकास (प्रथम चरण) का निर्माण।

[55] झा.र.श.वि. अधिनियम, 2016 (2016 का झारखंड अधिनियम संख्या 22) के माध्यम से।

पहले चरण में प्रशासनिक, शैक्षिक, पुस्तकालय और छात्रावास भवनों का निर्माण, और दूसरे चरण में शेष कार्य। पहले चरण में भवनों के निर्माण के लिए ₹118.98 करोड़ की राशि के बी.ओ.क्यू. को महाप्रबंधक, झा.रा.भ.नि.नि.लि. द्वारा अनुमोदित (फरवरी 2018) किया गया था। पहले चरण के अंतर्गत कार्यों के लिए निविदा के बाद, प्रबंधक, प.का.इ., खूंटी ने 24 महीने के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए एक संवेदक के साथ ₹107.08 करोड़ मूल्य का एक अनुबंध निष्पादित किया (जून 2018)।

हालांकि, यह देखा गया कि विभाग ने मुख्यमंत्री, झारखंड की अध्यक्षता वाली एक समिति के निर्देशों (दिसंबर 2020) पर कंपनी को झा.र.श.वि. के लागू पाठ्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए झा.र.श.वि. के लिए स्थायी परिसर के निर्माण को निलंबित करने का निर्देश दिया था (मई 2021) ताकि विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी परिसर की स्थापना की आवश्यकता का पता लगाया जा सके। तदनुसार, कंपनी ने प.का.इ., खूंटी को तत्काल प्रभाव से कार्य को निलंबित करने का निर्देश दिया (जून 2021)। विभाग से किसी भी आगे के निर्देश के अभाव में, आंशिक रूप से पूर्ण (19 प्रतिशत) होने के बाद, प.का.इ., खूंटी द्वारा कार्य अंततः बंद कर दिया गया (जुलाई 2021)। किए गए कार्यों के विरुद्ध संवेदक को ₹12.10 करोड़ (जुलाई 2022 तक) का भुगतान किया गया था और तब से अधूरी संरचना बेकार पड़ी हुई है।

इस प्रकार, चल रहे कार्य को निलंबित करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹12.10 करोड़ का अपव्यय हुआ।

परित्यक्त संरचनाओं को **चित्र 2.3** से **चित्र 2.6** में देखा जा सकता है।

चित्र 2.3	**चित्र 2.4**
चित्र 2.5	**चित्र 2.6**

झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, खूंटी (07.03.2024) की परित्यक्त भवन संरचनाएं

- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा 'रजरप्पा (रामगढ़) पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण पर्यटन विकास (पहला चरण)' योजना को ₹20.92 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी (जून 2018)। निविदा के बाद, प.का.इ., रामगढ़ ने अप्रैल 2020 तक कार्य को पूर्ण करने के लिए संवेदक के साथ ₹19.10 करोड़ मूल्य का एक अनुबंध निष्पादित किया (जनवरी 2019)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2022 तक 12[56] घटकों में से केवल तीन[57] घटकों का कार्य शुरू हुआ था।, कार्य के लिये निर्धारित स्थल वन भूमि पर होने के कारण कार्य के शेष घटक शुरू नहीं किए जा सके, जिसके लिए वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग से वन मंजूरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। हालांकि उपयोगकर्ता विभाग ने वन विभाग से वन मंजूरी प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया था (नवंबर 2019), लेकिन वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2023 तक)। कंपनी ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्र.अ. से शेष नौ घटकों को हटाने के लिए उपयोगकर्ता विभाग से अनुरोध किया था (अप्रैल 2022)।

जिन तीन घटकों में काम शुरू हुआ था, उनमें केवल दो *प्रतिशत* कार्य ही पूर्ण हुआ था और स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इसे रोकने (जनवरी 2020) से पहले ₹32.24 लाख का भुगतान किया गया था। कंपनी के प्र.नि. ने बाद में पुरानी दर पर काम के निष्पादन को जारी रखने में संवेदक की अक्षमता के बारे में उपयोगकर्ता विभाग को सूचित भी किया (अप्रैल 2022)

---

[56] (i) रांची राजमार्ग पर प्रवेश द्वार, (ii) चितरपुर प्रवेश पर प्रवेश द्वार, (iii) गोला प्रवेश पर प्रवेश द्वार, (iv) पुरुष शौचालय, (v) महिला शौचालय, (vi) बस टर्मिनल ए, (vii) बस टर्मिनल बी, (viii) वर्षा आश्रय, (ix) स्थल विकास, (x) सूचना केंद्र, (xi) प्रसाद स्टॉल और (xii) पुल।

[57] (i) रांची राजमार्ग पर प्रवेश द्वार, (ii) चितरपुर प्रवेश पर प्रवेश द्वार और (iii) पुल

क्योंकि तब तक काम दो साल से अधिक समय तक निलंबित कर दिया गया था।

इस प्रकार, परियोजना शुरू होने से पहले बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कंपनी की अक्षमता के कारण कार्य बंद हो गया और परिणामस्वरूप ₹32.24 लाख अपव्यय हुआ।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के मामले में बनाए गए बुनियादी संरचना की उपयोगिता के बारे में पुनर्विचार सरकारी स्तर पर चल रहा है और निर्मित बुनियादी ढांचे को नहीं छोड़ा गया है। इसके अलावा, रजरप्पा में पर्यटन विकास के मामले में, यह कहा गया था कि कार्य प्रगति पर है।

विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के मामले में अधूरी संरचनाएं तीन साल (जुलाई 2024 तक) से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं।

2.5.5.4 निष्फल व्यय

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सा.स्वा.के.), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के.), पर्यटन विकास कार्य, चारदीवारी के निर्माण और 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज से संबंधित छह कार्यों के निष्पादन के लिए चार उपयोगकर्ता विभागों द्वारा ₹ 24.01 करोड़ (दिसंबर 2007 और मार्च 2018 के बीच) का प्र.अ. दिया गया था। इनमें से, संबंधित विभागों द्वारा संवेदकों के साथ तीन कार्यों[58] के लिए ₹9.12 करोड़ मूल्य के अनुबंधो को निष्पादित किया गया था (दिसंबर 2007 और अप्रैल 2016 के बीच)। शेष तीन[59] कार्यों के लिए कंपनी द्वारा ₹11.99 करोड़ मूल्य के अनुबंध को निष्पादित किया गया था (दिसंबर 2016 और फरवरी 2019 के बीच)। बाद में, जिन कार्यों के लिए

---

[58] स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग: सा.स्वा.के. बरहरवा (साहिबगंज) और प्रा.स्वा.के. केश्वारी सरिया (गिरिडीह) और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के विभाग का निर्माण: सुतियाम्बे, पिथौरिया, रांची में पर्यटन विकास कार्यों का निर्माण

[59] रांची विश्वविद्यालय, चेदी के प्रस्तावित नए परिसर में चारदीवारी का निर्माण; रांची में 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण और प्रा.स्वा.के., खरसावां (सरायकेला-खरसावां) का निर्माण।

संबंधित विभागों द्वारा अनुबंध निष्पादित किए गए थे, उन्हें भी कंपनी को हस्तांतरित कर दिये गये थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन छह कार्यों को दिसंबर 2011 और मई 2020 के बीच पूर्ण किया जाना था। हालांकि, ₹13.33 करोड़ के व्यय के बाद कार्यों की भौतिक प्रगति ***(परिशिष्ट 2.8)*** 20 से 76 *प्रतिशत* के बीच थी (अक्टूबर 2023 तक)। आगे यह देखा गया कि:

- रांची में 5000-एम..टी कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए, उपयोगकर्ता विभाग द्वारा दिए गए ₹6.66 करोड़ के मूल प्र.अ. को दरों की अनुसूची (जुलाई 2016) में परिवर्तन के कारण संशोधित कर ₹7.73 करोड़ तक किया गया था (मार्च 2018)। इसके अलावा, परामर्शी ने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए निष्पादन के दौरान प्रशीतन प्रणाली में बदलाव (अमोनिया गैस के बजाय उपयोग की जाने वाली फ्रीऑन गैस) का प्रस्ताव दिया था। एक स्वतंत्र पुनरीक्षण एजेंसी, बिरला तकनीकी संस्थान (बी.आई.टी.), मेसरा, रांची ने भी फरवरी 2019 में समझौते के बाद नक्शा एवम रूपांकण में बदलाव का सुझाव दिया था। तदनुसार, नक्शा मे परिवर्तन के आलोक में नई मदों को जोड़ने के कारण ₹7.73 करोड़ के प्राक्कलन को फिर से संशोधित कर ₹9.13 करोड़ कर दिया गया (अप्रैल 2021)। हालांकि, उपयोगकर्ता विभाग से कंपनी द्वारा ₹9.13 करोड़ का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन मांगा गया था (अगस्त 2021 और नवंबर 2022), पर वह नहीं दिया गया था (जुलाई 2024 तक)। इस बीच, कंपनी ने कार्य का निष्पादन जारी रखा और जुलाई 2022 तक ₹5.05 करोड़ का व्यय किया। यह भी देखा गया कि संवेदक ने काम के निष्पादन को जारी रखने से इन्कार कर दिया था (नवंबर 2022) क्योंकि यह पुरानी दरों के साथ पिछले प्राक्कलनो पर आधारित था, और उपयोगकर्ता विभाग ने नई दरों के आधार पर संशोधित प्र.अ. की सहमति नहीं दी थी। इस प्रकार, कार्य को रोक दिया गया और ₹5.05 करोड़[60] का व्यय निष्फल रहा।

[60] संवेदक को भुगतान: ₹ 4.71 करोड़ और कंपनी का एजेंसी शुल्क: ₹ 0.34 करोड़।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि संशोधित प्र.अ. उपयोगकर्ता विभाग द्वारा दिया गया है और संवेदक को तुरंत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

उत्तर तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि संवेदक के साथ किया गया अनुबंध फरवरी 2025में समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा, संशोधित प्र.अ. केवल मार्च 2025में दिया गया था। इस प्रकार, नवंबर 2022 से काम बंद कर दिया गया है और आंशिक रूप से पूर्ण संरचना पर मार्च 2025 तक व्यय निष्फल रहा।

सा.स्वा.के. बरहरवा (साहिबगंज), प्रा.स्वा.के. खरसावां (सरायकेला-खरसावां) और प्रा.स्वा.के. केश्वारी-सारिया (गिरिडीह) का निर्माण ₹7.65 करोड़ की प्राक्कलित लागत से किया गया था और दिसंबर 2011 और फरवरी 2019 के बीच कार्यों को पूर्ण करने की शर्त के साथ दिसंबर 2007 और नवंबर 2017 के बीच अनुबंधो को निष्पादित किया गया था। 20 *प्रतिशत* से 76 *प्रतिशत* तक की भौतिक प्रगति के बाद, इन कार्यों को संवेदकों द्वारा रोक दिया गया था (सितंबर 2017 और दिसंबर 2020 के बीच) जिसके लिये अभिलेख मे कोई कारण उपलब्ध नहीं थे। हालांकि कंपनी ने कार्य को फिर से शुरू करने के लिए संवेदकों को कई अनुस्मारक जारी किए (फरवरी 2019 और जुलाई 2022 के बीच), पर इसने संवेदक को कार्य समाप्त करने या पुन: निविदा के माध्यम से शेष कार्य को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। फलस्वरूप, आंशिक रूप से पूर्ण की गई भवने जुलाई 2024 तक निष्क्रिय पड़ी थीं। कंपनी ने केवल अगस्त 2023 में सा.स्वा.के.,बरहरवा के अनुबंध को रद्द करने का प्रस्ताव दिया और केवल जनवरी 2023 में प्रा,स्वा.के., केश्वारी सारिया (गिरिडीह) के अनुंबंध को समाप्त कर दिया। इसके अलावा, इन तीन कार्यों को कंपनी द्वारा जुलाई 2024 तक नई निविदा के माध्यम से फिर से शुरू नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अनुबंधो को समाप्त करने/रद्द करने और नए सिरे से कार्य को निष्पादित करने के संबंध में निर्णय लेने में कंपनी द्वारा विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹4.17 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि अपेक्षित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि सा.स्वा.के., बरहरवा का संशोधित प्राक्कलन संशोधित प्र.स्वी. के लिये उपयोगकर्ता विभाग को भेजा गया था और 82 *प्रतिशत* पूरा होने के साथ कार्य प्रगति पर था। इसके अलावा, यह कहा गया था कि प्रा.स्वा.के., केश्वारी सरिया के मामले में संशोधित प्र.अ. प्राप्त करने के बाद निविदा जारी की जाएगी, जबकि प्रा.स्वा.के. खरसावां के मामले में, शेष कार्य के लिए संशोधित प्राक्कलन की तैयारी प्रगति पर है।

इस प्रकार, पूर्णता की मूल नियत तिथि से 12 साल तक के अंतराल के बावजूद, ये संरचनाएं अभी भी अधूरी पड़ी थीं (जुलाई 2024 तक), जिससे इच्छित लाभार्थियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है।

- रांची विश्वविद्यालय, चेदी के प्रस्तावित नए परिसर में चारदीवारी के निर्माण का कार्य (57 *प्रतिशत* की भौतिक प्रगति के बाद) स्थानीय लोगों के विरोध, निर्मित चारदीवारी को क्षति पहुंचाने, ईंटों की चोरी के कारण संवेदक द्वारा रोक दिया गया था (दिसंबर 2017)। तब तक, कंपनी द्वारा संवेदक को ₹1.95 करोड़ का भुगतान किया जा चूका था। संवेदक ने स्थानीय लोगों द्वारा पहुंचाये गये बाधाओं और क्षति के संबंध में कंपनी को सूचित किया था (अप्रैल 2018) और एक प्राथमिकी भी दर्ज की थी (जुलाई 2020)। कंपनी ने रांची के उपायुक्त से भी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था (सितंबर 2021) ताकि कार्य पूर्ण किया जा सके।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि स्थानीय बाधा के मुद्दे को हल करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

इस प्रकार, कार्य शुरू होने से पहले बाधा मुक्त भूमि प्रदान करने और कार्य स्थल पर उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने में कंपनी की अक्षमता के परिणामस्वरूप कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से छह वर्ष से अधिक समय तक (जुलाई 2024 तक) रुका रहा ।

- पिथौरिया, रांची में "सुतियाम्बे पहाड़ी[61] का विकास" का कार्य अक्टूबर 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन संवेदक ने तब तक केवल

[61] वाणिज्यिक केंद्र, शौचालय ब्लॉक, विश्राम कक्ष आदि

आठ *प्रतिशत* कार्य पूरा किया। कार्य की धीमी प्रगति के बावजूद, कंपनी ने कार्य के क्रियान्वयन को तेज करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, अगस्त 2020 में, संवेदक ने केवल 58 *प्रतिशत* कार्य पूरा करने के बाद 8 वें चा.ले. विपत्र का दावा किया (जुलाई 2020 में लिया गया माप) और कंपनी ने संवेदक के उसके इस वचन के साथ कि वह कार्य एक महीने के अंदर पूरा करेगा, विपत्र का भुगतान किया (नवंबर 2020)।इसके बाद, संवेदक ने कार्य पूरा नहीं किया (अक्टूबर 2023 तक) और कंपनी ने भी संवेदक के विरूध कोई कार्रवाई नहीं की। चूंकि आंशिक रूप से पूर्ण की गई संरचना तीन वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी हुई थी, इसलिए कार्य पर किए गए ₹ 2.16 करोड़ का व्यय निष्फल रहा है, क्योंकि अपेक्षित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

उत्तर में**,** विभाग ने कहा **(**जुलाई 2024**)** कि पिछले संवेदक द्वारा निष्पादित कार्य के अंतिम माप के बाद शेष कार्य के लिए नए स्तर से निविदा आमंत्रित किया गया है।

जवाब में संवेदक के विरूध कोई कार्रवाई नहीं करने और कार्य को फिर से शुरू करने में विलम्ब के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं किया गया।

2.5.5.5 संशोधित तकनीकी स्वीकृति और संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के बिना कार्य का निष्पादन

झा.लो.नि.वि. संहिता के नियम 123 के अनुसार, उन मामलों में संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है जहां तैयार किया गया विस्तृत प्राक्कलन की राशि, मूल रूप से अनुमोदित राशि से 20 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, झा.लो.नि.वि. सन्हिता के 293 (v) (i) के साथ पठित नियम 127 के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां बचत मूल रूप से अनुमोदित नक्शा से संरचनात्मक प्रकृति के भौतिक विचलन के कारण है, और संशोधित प्राक्कलन की राशि मूल प्राक्कलन की राशि से 20 प्रतिशत से अधिक है, सक्षम पदाधिकारी से एक संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परामर्शी ने एक कार्य[62] के लिए ₹348.50 करोड़ की राशि का एक वि.प.प्र. तैयार किया था (जुलाई 2017), जिसे कंपनी द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित (नवंबर 2017) किया गया था। उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग द्वारा ₹348.50 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था (नवंबर 2017) और कार्य को दो चरणों में निष्पादित किया जाना था। चरण-I में, प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन और आस-पास के कार्यों के साथ कुलपति के बंगले के निर्माण से संबंधित कार्य निष्पादित किया जाना था, जबकि चरण-II में छात्रावास भवन, स्थल विकास कार्य, आवास आदि का निर्माण शामिल था।

कंपनी ने कार्य के पहले चरण-I के लिए ₹155.51करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) प्रदान की थी (फरवरी 2018) और इसे जुलाई 2020 की निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ ₹146.62 करोड़ की अनुबंधित लागत पर संवेदक को आवंटित किया गया था (जुलाई 2018)। यह देखा गया था कि चरण-I का कार्य, विस्तारित समय अवधि (जून 2022) के दौरान ₹189.89 करोड़ (₹5.67 करोड़ के एजेंसी शूल्क सहित) की लागत से पूर्ण किया गया था। चूंकि कार्य की लागत मूल स्वीकृत प्राक्कलन (₹155.51 करोड़) से 20 *प्रतिशत* से अधिक थी, इसलिए संशोधित त.स्वी. की आवश्यकता थी, लेकिन अक्टूबर 2023 तक कंपनी द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया था। इसके अलावा, एक नए समझौते के माध्यम से यात्री लिफ्टों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग और भूनिर्माण कार्य के लिए संवेदक को ₹ 5.56 करोड़ का भुगतान (मार्च 2023) किया गया। इस प्रकार, उपयोगकर्ता विभाग द्वारा दोनों चरणों के लिए ₹197.04 करोड़ के कुल आवंटन की तुलना में कंपनी द्वारा कार्य के चरण-I पर ₹195.45 करोड़ का कुल व्यय किया गया था (जनवरी 2024 तक)।

इसके अलावा, चरण-II के कार्यों के लिए ₹262.79 करोड़ (जून 2023 के एस.ओ.आर. के आधार पर) का एक नया वि.प.प्र. परामर्शी द्वारा प्रस्तुत किया गया था (जनवरी 2024) और कंपनी ने तकनीकी अनुमोदन (जनवरी 2024) दिया था। चूंकि पूरी परियोजना की लागत बढ़कर ₹458.24 करोड़

[62] धनबाद में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का निर्माण।

हो गई थी (अर्थात ₹ 348.50 करोड़ के मूल प्र.स्वी. की तुलना में 31 *प्रतिशत* अधिक), कंपनी को उपरोक्त उल्लिखित सन्हिता प्रावधान के अनुसार उपयोगकर्ता विभाग से संशोधित प्र.अ. प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि, यह ध्यान दिया गया था कि जुलाई 2024 तक विभाग द्वारा संशोधित प्र.अ. नहीं दिया गया था और कार्य के चरण-II के लिए ₹261.20 करोड़ (₹458.24 करोड़ घटाव ₹197.04 करोड़) की अतिरिक्त धनराशि प्रदान नहीं की जा सकी, जिससे कार्य पूरा नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने कार्य के चरण-I के लिए अनुमोदित अनुमानित लागत से अधिक धनराशि खर्च करने से पहले उपयोगकर्ता विभाग को अवगत नहीं कराया था और उनसे संशोधित प्र.अ. भी प्राप्त नहीं कर सकी थी। इसके परिणामस्वरूप संशोधित प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ तथा चरण-I के तहत निर्मित पूर्ण संरचनाओं के साथ परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी और निष्क्रिय पड़ी रही (जुलाई 2024 तक)।

उत्तर में**,** विभाग ने कहा **(**जुलाई 2024**)** कि कार्य के दूसरे चरण के निष्पादन से पहले उपयोगकर्ता विभाग से संशोधित प्र.अ. प्राप्त किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चरण-**I** कार्य के पूरा होने के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद**,** चरण-**II** के कार्य शुरू नहीं किए गए थे **(**जुलाई 2024 तक**)** और चरण **I** के तहत पूरा किए गए कार्य निष्क्रिय रहे।

अनुशंसा 5: कंपनी लागू नियमों के तहत उपयोगकर्ता विभागों के संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संशोधित प्राक्कलन को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकती है, ताकि कार्य समय सीमा के अनुसार पूरा हो सके।

2.5.5.6 रॉयल्टी की कम कटौती

संवेदकों द्वारा कार्यों में निर्माण सामग्री (स्टोन चिप्स, स्टोन मेटल, मिट्टी, रेत और भट्ठी ईंट) के उपयोग के लिए जिला खनन अधिकारियों द्वारा जारी रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र कंपनी को प्रस्तुत करना आवश्यक था, ऐसा न करने पर कंपनी को संवेदकों के भुगतान से दंडात्मक दर (रॉयल्टी

की निर्धारित दर से दोगुनी) से रॉयल्टी कटौती करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, सितंबर 2019 से, निर्माण सामग्री के लिए रॉयल्टी की दरों को संशोधित किया गया था। मा.बो.द. (खंड 43.1) के प्रावधान के अनुसार, भुगतान को स्रोत पर कर एवं अनुबंध के संदर्भ में अग्रिम भुगतान, प्रतिधारण, अन्य वसूलियों हेतु कटौती के लिए समायोजित किया जाना था, जैसा कि कानून के तहत लागू हो।

सितंबर 2019 से फरवरी 2023 की अवधि के दौरान, चार मामलों में, कंपनी ने उन कार्यों में उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की मात्रा पर रॉयल्टी की पुरानी दरों को लागू करके संवेदक से ₹95.97 लाख की रॉयल्टी की कटौती की, जिसके लिए रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने रॉयल्टी की गणना नई दरों पर की और पाया कि ₹1.20 करोड़ संवेदकों के भुगतान से वसूली योग्य था। इस प्रकार, ₹ 23.75 लाख की रॉयल्टी की कम कटौती हुई, जैसा कि **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: रॉयल्टी की कम कटौती

(₹लाख में)

क्रम सं.	**कार्य का नाम**	**रॉयल्टी वसूली योग्य**	**रॉयल्टी काटी गई**	**रॉयल्टी की कम कटौती**
1	खिजरी, रांची में डिग्री कॉलेज का निर्माण	21.78	18.01	3.77
2	छतरपुर, पलामू में डिग्री कॉलेज का निर्माण	36.44	24.61	11.83
3	महगामा, गोड्डा में डिग्री कॉलेज का निर्माण	25.79	19.32	6.47
4	बरही, हजारीबाग और गोमिया, बोकारो में डिग्री कॉलेजों का निर्माण	35.71	34.03	1.68
कुल		**119.72**	**95.97**	**23.75**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत सामग्री विवरण)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कंपनी ने दो कार्यों (क्रमांक 1 और 4) में ₹5.45 लाख की रॉयल्टी वसूल की थी (जनवरी 2024)। हालांकि, अन्य दो कार्यों (क्रमांक 2 और 3) के संबंध में ₹18.30 लाख की

शेष राशि की वसूली नहीं की गई है(जुलाई 2024 तक), जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है।

विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया **(**जुलाई 2024**)** और कहा कि शेष राशि संवेदकों से वसूल की जाएगी।

2.5.5.7 बैंक गारंटियों की निगरानी

मा.बो.द. अनुबंध (खंड 52.1) में यह प्रावधान है कि निष्पादन प्रतिभूति नियोक्ता को स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान की जानी है और इसे नियोक्ता को स्वीकार्य राशि और रुप में बैंक या जमानत द्वारा जारी किया जाना चाहिए। निष्पादन प्रतिभूति (अनुबंध मूल्य का दो प्रतिशत) दोष देयता अवधि की समाप्ति की तारीख से 28 दिनों तक वैध होगी (पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष)। यदि नियोजक को ऐसी राशि का भुगतान या प्रतिपूर्ति करनी पड़ती है, जो संवेदक की ओर से अधिसूचनाओं/उपनियमों/अधिनियमों/नियमों/विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का पालन करने या न करने के लिए आवश्यक हो, जिसमें संशोधन भी शामिल हैं, यदि कोई हो, तो इंजीनियर/नियोजक को संवेदक को देय किसी भी धनराशि को काटने का अधिकार होगा, जिसमें उसकी निष्पादन प्रतिभूति राशि भी शामिल है। नियोक्ता/अभियंता को नियोक्ता को हुए नुकसान या क्षति को पूरा करने के लिए आवश्यक या अनुमानित किसी भी राशि को संवेदक से वसूल करने का भी अधिकार होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने चार निर्माण कार्यों (**तालिका 2.7**) के लिए बैंक गारंटी (बी.जी.) के रूप में ₹1 करोड़ (₹50.11 करोड़ के सहमत मूल्य का दो *प्रतिशत*) की निष्पादन प्रतिभूति स्वीकार की थी, जिसे अप्रैल 2019 और दिसंबर 2022 के बीच पूरा किया जाना था। संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार, बी.जी. को मई 2020 से जनवरी 2024 तक वैध होना आवश्यक था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बी.जी. की वैधता नवंबर 2018 और जनवरी 2023 के बीच समाप्त हो गई थी, हालांकि कार्य अपूर्ण थे (जुलाई 2024 तक)। कंपनी ने कम वैधता अवधि के साथ बी.जी. को स्वीकार किया था और संवेदकों से पूरी अवधि (दोष देयता तिथि से 28

दिनों तक) के लिये नई निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

तालिका 2.7: निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी

कार्य का नाम	सहमत मूल्य (₹करोड़ में)	पूरा होने की निर्धारित तिथि	आवश्यक निष्पादन प्रतिभूति (₹लाख में)	अपेक्षित वैधता	जारी करने वाला बैंक/जारी करने की तिथि	तक वैध
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, मानातु, पलामू का निर्माण	11.34	अप्रैल 2019	22.68	मई 2020	भारतीय स्टेट बैंक, पलामू/28.11.2017	नवंबर 2018
5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज, सेन्हा, लोहरदगा का निर्माण	7.40	फरवरी 2020	14.80	मार्च 2021	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, /07.10.2018	दिसंबर 2022
	1.21 (अनुपूरक)	दिसंबर 2022	2.42	जनवरी 2024		जनवरी 2023
पलामू में 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण	7.51	नवंबर 2020	15.02	दिसंबर 2021	भारतीय स्टेट बैंक, रांची	जुलाई 2020
गुमला में पेलेटेड पोल्ट्री फीड प्लांट, ब्रॉयलर, ब्रीडर फार्म और लेयर पोल्ट्री फार्म का निर्माण	22.65	मार्च 2021	45.30	अप्रैल 2022	-----	अक्टूबर 2020
कुल	**50.11**		**100.22**			

इस प्रकार, कम वैधता अवधि की निष्पादन प्रतिभूति की स्वीकृति और बी.जी. को नियमित रूप से पुनर्वैधीकरण कराने में असमर्थता के कारण, कंपनी कार्य के संबंध में, विशेष रूप से दोष देयता अवधि के दौरान नुकसान या क्षति को पूरा करने के लिए आवश्यक या अनुमानित किसी भी राशि की संवेदक से वसूली करने की स्थिति में नहीं थी।

उत्तर में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2024) कि प.का.इ. को समझौते के समय दोष देयता अवधि से आगे 28 दिनों तक के लिए बी.जी. लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2.5.5.8 मोबिलाइजेशन अग्रिम के प्रबंध में अनियमितताएं

मा.बो.द. के प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ता को बिना शर्त बैंक गारंटी जमा करने पर संवेदक को अनुबंध मूल्य के 10 *प्रतिशत* अग्रिम भुगतान करना था (अनुबंध अवधि के 20 *प्रतिशत* के बीतने से पहले निकासी किया जाना है)। इसके अलावा, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, अग्रिम ऋण को

अभियंता द्वारा प्रमाणित अंतरिम भुगतान से प्रतिशत कटौती के साथ चुकाया जाना था। कटौती अगले अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र से शुरू होनी थी, यदि ऐसे भुगतान अनुबंध मूल्य के 20 प्रतिशत से कम नहीं थे, या अग्रिम की पहली किस्त के भुगतान की तारीख से छह महीने, जो भी पहले हो, और हमेशा यह प्रावधान था कि ऋण को पूरा करने के लिए मूल समय की समाप्ति से पहले पूरी तरह से चुकाया जाएगा। इसके अलावा, छह महीने के बाद शेष अग्रिम पर 10 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाना था।

उपयोगकर्ता विभाग[63] ने सात कार्यों के लिए ₹3,326.02 करोड़ की राशि के लिये प्र.अ. दी थी (सितंबर 2016 और दिसंबर 2017 के बीच) ***(परिशिष्ट 2.9)*** और कंपनी ने फरवरी 2019 से दिसंबर 2021 के बीच पूर्ण किए जाने वाले कार्यों के लिए संवेदकों के साथ ₹2,431.53 करोड़ मूल्य के अनुबंधो को निष्पादित किया था (जनवरी 2017 और जून 2019 के बीच)। अनुबंधो को निष्पादित करने के बाद, कंपनी ने प्राप्त बी.जी. के विरूद्ध सात कार्यों के लिए ₹141.40 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया (मार्च 2017 और मार्च 2021 के बीच) और संवेदकों को किए गए अंतरिम भुगतान से पूरी राशि वसूल कर ली थी (मई 2019 और मार्च 2023 के बीच)। इन सात कार्यों में से तीन कार्य[64], जून 2022 और दिसंबर 2022 के बीच पूर्ण किए गए, जिसके लिये ₹1,138.59 करोड़ की राशि का भुगतान संवेदकों को किया गया था। शेष चार कार्य[65] ₹533.44 करोड़ का व्यय करने के बाद प्रगति पर थे। ये कार्य 22 से 40 महीने की विलम्ब के साथ निर्धारित समय सीमा पार कर चुके थे। लेखापरीक्षा ने उपर्युक्त कार्यों के संदर्भ में कंपनी द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम के प्रबंध में निम्नलिखित अनियमितताओं को देखा:

---

63 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग (पांच कार्य) और उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग (दो कार्य)।

64 पलामू, हजारीबाग और दुमका में मेडिकल कॉलेज; रांची में 500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल और धनबाद में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का शेष कार्य।

65 दुमका, हजारीबाग और पलामू में मेडिकल कॉलेजों के तहत तीन 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और पलामू में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर में नए परिसर निर्माण।

- **अग्रिम का अनियमित भुगतान**

दो कार्यों[66] में, कंपनी ने संवेदकों को ₹26.24 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम (नवंबर 2018 और अगस्त 2019 के बीच) भुगतान किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन अग्रिमों को संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार अनुबंध अवधि के 20 *प्रतिशत* के अंत से पहले तैयार किया जाना आवश्यक था अर्थात 3 दिसंबर 2018 और 7 मई 2019 के बीच। जबकि कंपनी ने निर्धारित अवधि के भीतर ₹17.32 करोड़ दिए (अर्थात 3 दिसंबर 2018 से 7 मई 2019 के बीच), शेष अग्रिम ₹8.92 करोड़ का भुगतान प्रत्येक मामले में 20 *प्रतिशत* से अधिक कार्य पूरा होने के बाद किया गया था। अनुबंध अवधि के 20 प्रतिशत की समाप्ति के बाद संवेदकों को मोबिलाइजेशन अग्रिम देने से कार्य के प्रारंभिक चरण में कार्य स्थल पर संयंत्र और मशीनरी लाने के जैसे इसके उद्देश्य को विफल कर दिया।

उत्तर में**,** विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा **(**जुलाई 2024**)** कि इसे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट किया गया है।

- **मोबिलाइजेशन अग्रिम के पुनर्भुगतान में विलम्ब**

चार कार्यों[67] में, बी.जी. जमा करने के विरूद्ध ₹57.12 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया गया था (दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2019 के बीच)। इन अग्रिमों की वसूली संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार अग्रिम की पहली किस्त देने की तारीख से छह महीने बाद, जून 2018 और अप्रैल 2020 के बीच शुरू होनी थी। हालांकि, कंपनी ने इन चार कार्यों में, चार से सात महीने तक के विलम्ब के साथ संवेदकों से अग्रिम की वसूली (सितंबर 2018 और सितंबर 2021) शुरू की। इसके अलावा, संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार, पूरा अग्रिम, कार्य पूर्ण होने की प्रारंभिक निर्धारित तिथि के अंदर वसूल किया जाना था। हालांकि, कंपनी ने पूर्णता की प्रारंभिक निर्धारित

---

66 धनबाद में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और मेदिनीनगर, पलामू में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय में नया परिसर भवन।

67 (1) मेडिकल कॉलेज, पलामू मे 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण (2) रांची में 500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल का शेष कार्य और (3) मेडिकल कॉलेज हजारीबाग मे 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण और (4) नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू के लिए नया परिसर भवन

तिथि (फरवरी 2019 और दिसंबर 2021 के बीच) के भीतर इन कार्यों में संवेदकों को दिए गए ₹57.12 करोड़ की अग्रिम में से केवल ₹16.30 करोड़ की वसूली की।

इस प्रकार, ₹40.82 करोड़ का शेष अग्रिम 13 से 27 महीने तक के विलम्ब के साथ वसूल किया गया था। ***(परिशिष्ट 2.10 और 2.11)***।

उत्तर में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि नियत तिथि पर अग्रिम की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि कार्य पूरा करने में विलम्ब हुई थी और संवेदक ने कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि के भीतर विपत्र जमा नहीं किए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी संवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी से अग्रिम भुगतान की वसूली कर सकती थी।

अनुशंसा 6: कंपनी समझौते की शर्तों और मौजूदा लागू नियमों के अनुसार संवेदकों को मोबिलाइजेशन अग्रिमों का संवितरण और वसूली सुनिश्चित कर सकती है।

2.5.5.9 समय और लागत में वृद्धि

2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान 21 प.का.इ./प्रमंडलो द्वारा निष्पादित मेडिकल कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों, सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के., झा.बा.आ.वि., एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयो आदि के निर्माण से संबंधित नमूना-जांचित 94 कार्यों में से 47 कार्यों मे लेखापरीक्षा ने समय वृद्धि पाया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- नौ उपयोगकर्ता विभागों द्वारा 47 कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 3,938.91 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था (फरवरी 2014 और जुलाई 2019 के बीच)। तदनुसार, कंपनी द्वारा दिसंबर 2015 और फरवरी 2024 के बीच कार्यों को पूर्ण करने के लिए संवेदकों के साथ ₹3,114.24 करोड़ मूल्य के अनुबंधो को (जून 2014 और दिसंबर 2019 के बीच) निष्पादित किया गया था।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन से 46 महीनों तक के विलम्ब के साथ ₹1,693.31 करोड़ का व्यय करने के बाद 33 कार्य (फरवरी 2017 और फरवरी 2024 के बीच) पूर्ण किए गए थे।
- ₹669.98 करोड़ के व्यय और निर्धारित पूर्णता तिथि से 23 से 89 महीने (अक्टूबर 2023 तक) के विलम्ब के बाद 14 कार्य अपूर्ण थे। स्थल की स्थितियों के आधार पर विस्तृत प्राक्कलनो के बजाय मॉडल प्राक्कलनो पर कार्य शुरू करने, स्थल विशिष्ट नक्शा और रूपांकण उपलब्ध करने में विलम्ब और अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक निर्धारित समय के भीतर कार्यों को पूर्ण नहीं करने के लिए संवेदकों के विरूद्ध कंपनी द्वारा कार्रवाई की कमी के कारण ये कार्य अपूर्ण रहे। इसके परिणामस्वरूप कार्य पूर्णता मे तीन से 89 महीने ***(परिशिष्ट 2.12 ए*** और ***2.12 बी)*** तक की समय वृद्धि हुई**।**

उत्तर में**,** विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा **(**जुलाई 2024**)** कि कार्य भविष्य में निर्धारित समय के भीतर पूर्ण किये जाएंगे।

- दो विभागों[68] द्वारा ₹1,718.37 करोड़ के लिए छह कार्यों को प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था (फरवरी 2014 और दिसंबर 2017 के बीच) जिसके लिए कंपनी द्वारा संवेदकों के साथ अनुबंधो (₹1584.47 करोड़ के लिए) को निष्पादित किया गया था (जुलाई 2014 और जून 2019)। कार्यों के पूर्ण होने की निर्धारित तारीखें जुलाई 2016 और दिसंबर 2021 के बीच थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल दो कार्य 44 महीने तक के विलम्ब के साथ पूर्ण किए गए थे, जबकि चार कार्य 32 से 96 महीने (जुलाई 2024 तक) के विलम्ब के साथ अपूर्ण रहे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कार्य स्थलों को सौंपने में विलम्ब, नक्शा और रूपांकण उपलब्ध कराने में विलम्ब आदि जैसे विभिन्न कारणों से कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हुई। सभी छह मामलों में संवेदकों को समय विस्तार की अनुमति दी गई थी और इस विस्तारित अवधि के दौरान मूल्य समायोजन के रूप में ₹42.32 करोड़ का भुगतान किया गया

[68] स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग: 05 और कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग: 01

था, जिसके परिणामस्वरूप इन छह कार्यों ***(परिशिष्ट 2.12 सी)*** में इस राशि से लागत में वृद्धि हुई थी।

अनुशंसा 7: कंपनी उन मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कर सकती है जो समय और लागत में वृद्धि से बचने के लिए अनुबंधो के प्रावधानों के अनुसार कार्यों को समय पर पूर्ण करने में बाधा डाल रहे हैं।

2.5.5.10 पूर्ण भवनो का विलम्बित हस्तांतरण/अहस्तांतरण

निर्मित परिसंपत्तियों के समय पर उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि पूर्ण की गई परियोजनाएं/कार्य पूरा होने के तुरंत बाद संबंधित उपयोगकर्ता विभागों को हस्तांतरित कर दिए जाएं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान, नमूना-जांचित 94 कार्यों में से 46 पूर्ण हो चुके थे और नौ उपयोगकर्ता विभागों[69] से संबंधित 37 भवनो को पूरा होने के बाद 837 दिनों तक के विलम्ब के साथ उपयोगकर्ता विभागो को हस्तांतरित किया गया था **(परिशिष्ट 2.13)**। कार्य हस्तांतरण में विलम्ब का प्रमुख कारण उपयोगकर्ता विभागों और कंपनी के बीच समन्वय की कमी थी

शेष नौ भवनो को उनके पूरा होने के बाद से *1,414* दिनों की समाप्ति के बाद भी, अक्टूबर *2023* तक उपयोगकर्ता विभागों को हस्तांतरित नहीं किया गया था। कंपनी द्वारा उपयोगकर्ता विभागों के साथ प्रयास करने के बावजूद, विभागों ने भवनो को हस्तगत नहीं लिया जिसके कोई कारण अभिलेखित नही थे। लंबी अवधि के लिए पूर्ण परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नही करने से न केवल भवनो की स्थिति में गिरावट का जोखिम बढ़ता है, बल्कि इच्छित लाभार्थियों को इन भवनो के उपयोग से भी वंचित करता है।

---

[69] उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास; स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण; पर्यटन, कला और संस्कृति, खेल और युवा विकास; सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास; सूचना प्रौद्योगिकी और ई-शासन; अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग; स्कूल शिक्षा और साक्षरता; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास और अन्य

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कंपनी द्वारा *₹ 22.11* करोड़ के मूल्य पर एक कार्य[70] को मई 2019 तक पूर्ण करने हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया था *(मई 2017)*। संवेदक को *₹31.19* करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और फरवरी *2020* तक की दोषपूर्ण देयता अवधि के साथ कार्य पूर्ण हो गया था *(फरवरी 2019)*। कार्य पूर्ण होने के बाद, प.का.इ., जमशेदपुर ने कंपनी से उपयोगकर्ता विभाग को भवन सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था *(फरवरी 2019)*। हालांकि, कंपनी के अभिलेख के अनुसार, उपयोगकर्ता विभाग[71] ने कंपनी द्वारा कई बार अनुरोध *(अप्रैल 2020* और अक्टूबर *2021* और सितंबर *2022* के बीच*)* किए जाने के बावजूद परियोजना को हस्तगत लेने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। प.का.इ., जमशेदपुर ने इस बीच *(जनवरी 2022)* एक प्राथमिकी दर्ज की थी और बताया था कि कई उपकरण, अर्थात, बिजली के पंखे, बिजली के तार, आदि भवन से चुराए गए थे। कंपनी द्वारा मरम्मत कार्यों और चोरी हुई सामग्री को फिर से क्रय करने के लिए *₹2.43* करोड़ का एक नया प्राक्कलन तैयार किया गया था *(सितंबर 2022)*। इसके आधार पर, उपयोगकर्ता विभाग ने मरम्मत कार्यों के लिए *₹2.43* करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन दिया *(जनवरी 2023)* और सितंबर *2024* तक यह कार्य प्रगति पर था।

लेखापरीक्षा और कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन *(09* सितंबर *2023)* के दौरान, वॉश बेसिन से पानी के नल चोरी / गायब पाए गए और फर्नीचर क्षतिग्रस्त पाया गया जैसा कि **चित्र *2.7*और चित्र *2.8*** से देखा जा सकता है।

***चित्र* 2.7**	***चित्र* 2.8**

[70]. जमशेदपुर में प्रोफेशनल कॉलेज का निर्माण

[71] उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग

प्रोफेशनल कॉलेज, जमशेदपुर में क्षतिग्रस्त वॉशरूम और फर्नीचर (09 सितंबर 2023)

इस प्रकार, उपयोगकर्ता विभागों और कंपनी के बीच समन्वय की कमी के कारण, पूर्ण भवनों को सौंपने में विलम्ब हुआ और सृजित परिसंपत्तियां पूर्ण होने के बाद से निष्क्रिय रहीं। इसके अलावा, मरम्मत/पुनर्खरीद पर ₹2.43 करोड़ के व्यय को बचाया जा सकता था।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि उपयोगकर्ता विभाग से पूर्ण की गई परियोजनाओं को लेने का अनुरोध किया गया था।

अनुशंसा 8: राज्य सरकार कंपनी और उपयोगकर्ता विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर सकती है ताकि पूर्ण की गई भवनो को बिना किसी विलम्ब के सौंप दिया जा सके और इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके।

2.5.6 गुणवत्ता प्रबंध

कंपनी के व्यवसाय के नियमों के अनुसार, सभी वि.प.प्र./परियोजनाओं के तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में गंभीर रूप से मूल्यांकन करने के लिए, सभी स्वीकृत परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति की अनुश्रवण करने, काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसके लिये सुधारात्मक कार्रवाई आदि का सुझाव देने के लिये कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति[72] का गठन किया जाना था। ।

इसके अलावा, निदेशक मंडल (नि.मं.) ने अपनी 7 वीं बैठक (जुलाई 2018) में संकल्प किया था कि परियोजनाओं में उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का प्रयोगशालाओं के माध्यम से पूर्व-परीक्षण किया जाएगा और इस हेतु परीक्षण प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने के लिए प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया था। नि.मं. ने अपनी 10वीं बैठक (जुलाई 2020) में कंपनी द्वारा निष्पादित कार्यों के नक्शो और रूपांकणो की समीक्षा के लिए चार संरचनात्मक इंजीनियरों, एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सी.ए.डी.) ऑपरेटर, एक विद्युत इंजीनियर और चार ड्राफ्ट्समैन के साथ एक इन-हाउस रूपांकण शाखा बनाने का भी निर्णय लिया। हालांकि,

[72] का.नि.: अध्यक्ष, म.प्र. (परियोजना): सदस्य, म.प्र. (योजना): सदस्य, म.प्र. (परामर्शी): सदस्य और सभी क्षेत्रीय प्रबंधक: सदस्य।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने जुलाई 2024 तक न ही आवश्यक तकनीकी समिति का गठन किया था, न ही इसने परीक्षण प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया था या रूपांकण शाखा बनाया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तकनीकी समिति की अनुपस्थिति में, कंपनी ने वि.प.प्र. तैयार करने के लिए परामर्शी को नियुक्त किया था, और तकनीकी समिति द्वारा वि.प.प्र. का मूल्यांकन किए बिना, उनके द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलनो के आधार पर कार्य शुरू किया था। इसके अलावा, परीक्षण प्रयोगशालाओं के पैनल के अभाव में, पूर्व-परीक्षण की गई निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामलों को देखा जहां कार्य की इष्टतम गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी:

- पाकुड़ में 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का कार्य सितंबर 2022 में पूर्ण हो गया था और उक्त कार्य के लिए संवेदक को ₹10.44 करोड़ का भुगतान किया गया था। हालांकि पूर्ण भवन को सौंपने की प्रक्रिया मार्च 2023 में शुरू की गई थी, लेकिन उपयोगकर्ता विभाग द्वारा इसे नहीं लिया गया था जिसका कारण अभिलेख मे उपलब्ध नहीं थे। कंपनी ने कार्य का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया था (31 मई 2023)। समिति ने (14 जून 2023) पूर्ण किए गए कार्य में दोष अर्थात स्तंभों में मधुमक्खी छत्ते, स्तंभ बीम जंक्शनों में दरारें, अधूरे विस्तार जोड़, अनुचित उच्च-तनाव पैनल कार्य आदि, पाया। उस समय यह भी देखा गया कि अंतिम विपत्र का भुगतान संवेदक को यह सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया था (जून 2023) कि दोषों को ठीक किया गया था। कंपनी ने संवेदक को दोषों को सुधारने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2023) ताकि पूरी की गई संरचना उपयोगकर्ता विभाग को सौंप दी जा सके।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि सुधार कार्य किया गया है और भवन को हस्तगत लेने के लिए उपयोगकर्ता विभाग को अनुस्मारक जारी किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्ण किया गया भवन उपयोगकर्ता विभाग को नहीं सौंपा जा सका और दो वर्षों से अधिक समय

से निष्क्रिय पड़ा हुआ था, जो इसकी स्थिति में गिरावट के जोखिम से भरा हुआ था।

- जमशेदपुर महिला कॉलेज के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया था (जनवरी 2021) और कंपनी द्वारा संवेदक को ₹81.43 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। कार्य के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र भी कंपनी द्वारा 'बहुत अच्छी स्थिति' टिप्पणी के साथ जारी किया गया था (मार्च 2021)। हालांकि, उपयोगकर्ता विभाग की कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ने एक निरीक्षण (जनवरी 2021) के दौरान पाया कि वि.प.प्र. मे प्रावधान होने के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, का निर्माण नहीं किया गया था, प्लास्टर और दरवाजा का कार्य आदि की गुणवत्ता खराब थी और आंतरिक आंगन कई स्थानों पर टूटा हुआ पाया गया था। इसके अलावा, कंपनी के अधिकारियों ने स्थल का दौरा किया (दिसंबर 2021) और कई दोषों को देखा जैसे, भवन की दीवारों पर दरारें, जल संयोजन की अनुपलब्धता, अनुचित रूप से स्थापित पंखे, छात्रावास भवन के वॉशरूम में टूटी टाइलें आदि। इन दोषों को संवेदक द्वारा ठीक किया गया था और भवन को इसके पूरा होने के लगभग एक वर्ष बाद उपयोगकर्ता विभाग को (दिसंबर 2021) सौंपा जा सका था।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि दोषों के सुधार के बाद परियोजना उपयोगकर्ता विभाग को सौंप दी गई थी। हालांकि, गुणवत्ता कार्य के निष्पादन को सुनिश्चित करने से पहले पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के कारण नहीं बताये गए थे।

- राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में पुस्तकालय भवन का कार्य कंपनी द्वारा किया गया था और मई 2022 में ₹ 27.66 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया था और कंपनी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था (मई 2022)। हालांकि, तीसरे पक्ष के निरीक्षण (नवंबर 2022) के दौरान 5.50 मि.मी. ग्लास पेन के स्थान पर 4 मि.मी. का ग्लास पेन, सी.पी.वी.सी. पाईप के स्थान पर यू.पी.वी.सी. पाईप, सौर पैनल के विभिन्न ब्रांड आदि का उपयोग जैसे दोष देखे गए। हालांकि, दोषों का सुधार करने से पहले और पूर्ण भवन को आधिकारिक रूप से सौंपने से पहले

कंपनी ने रिम्स को भवन का उपयोग शुरू करने की अनुमति दे दी (सितंबर 2022)।

इस प्रकार, पूर्ण किए गए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था और अंतिम भुगतान किया गया था।

कंपनी/विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसा 9:कंपनी कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रूपांकण शाखा की स्थापना के साथ प्रयोगशालाओं का पैनल बनाना सुनिश्चित कर सकती है।

2.5.7 आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अपर्याप्त प्रणाली और वार्षिक सामान्य बैठके (ए.जी.एम.) और निदेशक मंडल (नि.मं) की बैठकों के आयोजन में विलम्ब का पता चला, जैसा कि नीचे बताया गया है।

- **आंतरिक लेखापरीक्षा**

व्यवसाय के नियमों (खंड 6ए) के अनुसार, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी थी, और नि.मं. को आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लेना था। आंतरिक लेखा परीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करना, कार्यालय प्रभारी के साथ अनियमितताओं पर चर्चा करना और अनसुलझे मुद्दों को कंपनी के प्र.नि. को प्रतिवेदित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने 2016-17 से 2017-18 की अवधि के लिए सी.ए. फर्म को अपने आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था (जून 2017)। उक्त फर्म को नि.मं. की बैठकों (जुलाई 2018 और सितंबर 2019) में लिए गए निर्णय के आधार पर 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए जारी रखने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए, कंपनी ने कोई आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया था। इस प्रकार, कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा केवल वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए की गई थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2024) कि कंपनी में लेखा कर्मियों की कमी के कारण आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

उत्तर ठोस नहीं है क्योंकि कंपनी लेखा कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए कार्रवाई कर सकती थी।

- **वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.)**

कंपनी के एसोसिएशन के लेख (खंड 41) में कहा गया है कि एक ए.जी.एम. की तारीख और उसके अगले बैठक की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 96 और 102), वार्षिक परिणामों, लेखा परीक्षक की नियुक्ति आदि पर चर्चा करने के लिए एक ए.जी.एम. आयोजित करने का प्रावधान करता है। एक कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के अंदर ए.जी.एम. आयोजित करनी चाहिए।

कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी की पहली ए.जी.एम. पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के छह महीने के अंदर यानि सितंबर 2016 में होनी चाहिए थी। हालांकि, झा.रा.भ.नि.नि.लि. ने कंपनी अधिनियम, 2013 का उल्लंघन करते हुए सितंबर 2019 में ही अपना पहला ए.जी.एम. आयोजित किया था। यह भी पाया किया गया कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम के उल्लंघन करते हुए 2015-16 और 2016-17 (सितंबर 2019 में) और 2017-18 और 2018-19 (दिसंबर 2020 में) के लिए चार ए.जी.एम. आयोजित किए थे, जबकि 2015-16 से 2022-23 की अवधि के लिए आठ ए.जी.एम. आयोजित किये जाने आवश्यक थे। इसके अलावा, पिछले ए.जी.एम. (दिसंबर 2020) के आयोजन के बाद से 15 महीने से अधिक समय बीत चुका था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए कंपनी ने दिसंबर 2020 के बाद ए.जी.एम. आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2024) कि भविष्य के लिए इसे नोट कर लिया गया है।

- **निदेशक मंडल (नि. मं) की बैठक**

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद (खण्ड 74) में कहा गया है कि नि.मं. प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा, ताकि वर्ष में कम से कम चार ऐसी बैठकें आयोजित की जा सकें। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 में कहा गया है कि लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 और 2022-23 के दौरान आवश्यक 32 बोर्ड बैठकों के खिलाफ 14 बैठकें आयोजित की थीं, जिसके लिये कोई कारण अभिलेखित नहीं किए गए थे। इसके अलावा, बोर्ड की 14 बैठकों में से, छह बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों की अनिवार्य अवधि से अधिक हो गया था अर्थात यह 257 से 364 दिनों के बीच था।

इस प्रकार, कंपनी ने निर्धारित संख्या से कम बोर्ड की बैठकों का आयोजन किया था। इसके अलावा, कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों (वर्ष 2015-16 से 2021-22 के लिए) के अनुमोदन में 11 से 36 महीने तक की विलम्ब हुई।

उत्तर में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया और कहा (जुलाई 2024) कि इसे भविष्य के लिए इसे नोट कर लिया गया है।

अनुशंसा 10: कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित की जाती है और नि.मं. की बैठकें/ए.जी.एम. नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

2.6 निष्कर्ष

कंपनी अपनी स्थापना के बाद से मार्च 2023 तक शुरू की गई 1,328 परियोजनाओं में से केवल 726 परियोजनाओं को पूर्ण कर सकी जबकि 218 कार्य प्रगति पर थे और 272 प्रारंभिक चरणों में थे। भूमि की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगो के विरोध, संवेदकों द्वारा किये गये विलम्ब आदि के कारण कुल 112 कार्यों को या तो छोड़ दिया गया था या रोक दिया गया था। वास्तविक स्थल की स्थितियों के आधार पर विस्तृत प्राक्कलनो के बजाय मॉडल प्राक्कलनो पर कार्य प्रारंभ करने, स्थल विशिष्ट नक्शा और रूपांकण

उपलब्ध करने में विलम्ब और अनुबंध के तहत आवश्यक निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण नहीं करने के लिए संवेदकों के विरूद्ध कंपनी द्वारा कार्रवाई की कमी के कारण नमना-जांचित 94 कार्यों में से 33 कार्य, 96 से 1,379 दिनों के बीच की विलम्ब के साथ पूर्ण किए गए और 14 कार्य, 681 से 2,678 दिनों (अक्टूबर 2023 तक) के विलम्ब के बावजूद अपूर्ण रहे। कंपनी ने 24 कार्यों जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था, के निष्पादन के लिए उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त ₹60.95 करोड़ वापस करने के बजाय, राशि को चार से सात साल की अवधि के लिए अपने पी.एल. खाता में रखी थी। वि.प.प्र./परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी समिति, जैसा कि परिकल्पित है, का गठन नहीं किया गया था और मॉडल प्राक्कलनो के आधार पर कार्य आरम्भ किए गए थे, जिससे कार्यों का परित्यजन और उसे पूर्ण करने मे समय/लागत की वृद्धि हुई। विशेष रूप से सहायक/कनीय अभियंताओं के प्रमुख पदों पर कार्यरत बल की अत्यधिक कमी के कारण कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसे अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने से रोका। लेखापरीक्षा ने अनुबंध प्रबंध में कमियों - बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय का प्रावधान; पारदर्शिता की कमी; अपर्याप्त बोली मूल्यांकन; अनुबंध के निष्पादन में विलम्ब; अनियमित भुगतान; पूरक अनुबंधो में अनियमितताएं; और कार्य का बीमा नही कराया जाना, को पाया। पूर्ण किए गए नमूना-जांचित 46 कार्यों में से, 37 कार्य 837 दिनों तक की विलम्ब के साथ उपयोगकर्ता विभागों को हस्तांतरित किये गए थे और शेष नौ कार्य उनके पूरा होने के बाद 1,414 दिनों के अंतराल के बाद भी हस्तांतरित नहीं किये गए थे। हस्तांतरण में विलम्ब का प्रमुख कारण उपयोगकर्ता विभागों और कंपनी के बीच समन्वय की कमी थी।